THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Please ascertain what the issue is now. Please ascertain what the status is now. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he has been arrested. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.K. HARIPRASAD: It is breach of privilege. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): We will examine it. ...*(Interruptions)*... We will examine it, Jairam Ramesh *ji*. ...*(Interruptions)*... Now, Prof. Ram Gopal Yadav.

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, ये हमें बोलने ही नहीं देंगे। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAVI PRAKASH VERMA (Uttar Pradesh): Sir, the House has to be in order first. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): The House is in order. ...*(Interruptions)*... We can hear him. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, we want to listen to our leader. ...*(Interruptions)*... हमारे नेता को बोलने के लिए वैसे ही कम समय मिला है। ...(**व्यवधान**)... Please bring the House to order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): If there is breach of privilege, we will examine it and we will take appropriate action. ...*(Interruptions)*... A senior Member is about to speak. Kindly extend him the courtesy. ...*(Interruptions)*... We will examine it. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: For Ram Gopal Yadav *ji*, we are keeping quiet. ...*(Interruptions)*...

GOVERNMENT BILLS

The National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019
and
The National Commission for Homoeopathy Bill, 2019 — *Contd.**

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सर, हमारे बोलने के लिए केवल 8 मिनट का समय है, जबकि हमें इस बिल पर बोलने के लिए एक घंटे का समय चाहिए था। इसीलिए आप मुझे कुछ ज्यादा टाइम दे दीजिएगा।

---

*Continued from 17 March, 2020.

सर, जो इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल 1970 की थी और होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल ऐक्ट, 1973 का था, इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए ये दोनों बिल लाए गए हैं। हैल्थ कमेटी ने इस पर अलग-अलग दो रिपोर्ट्स, 115वीं रिपोर्ट और 116वीं रिपोर्ट दी थी। इसमें इंडियन मेडिकल सिस्टम पर 37 recommendations की थीं और उन 37recommendations में से केवल 15 recommendations को स्वीकार किया गया है। इसी तरह से होम्योपैथी वाले बिल पर 24 recommendations दी थीं और उनमें से केवल 13 recommendations मानी गई हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं, उनको सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। मेरे पास बोलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

सर, एक तो हमारी हैल्थ कमेटी ने यह recommend किया था कि yoga और naturopathy को इसके purview में लाना चाहिए था, क्योंकि इसकी बहुत चर्चा होती है और सारी दुनिया में हम लोग विश्व गुरु होने की बात करते हैं और यह सही बात भी है, लेकिन उसको लाया नहीं गया है। इसके बारे में यह कहा गया है कि एक अलग से बिल आएगा। हमारी कमेटी ने यह कहा था कि जब तक बिल नहीं आता है तब तक एक yoga और naturopathy के लिए एक board create कर दिया जाए। यह सिफारिश भी नहीं मानी गई, जबकि यह करना चाहिए था। जब बिल आ जाता, तो यह अपने आप हट जाता। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने constitution of board of research के लिए recommendation भी की थी। महोदय, रिसर्च न होने से ही हमारी सबसे पुरानी जो विधा आयुर्वेद है, सिर्फ हमारी ही नहीं, बल्कि दुनिया की कहीं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि न जाने कितने समय से हम उसे देखते और सुनते चले आ रहे हैं, रिसर्च न होने से ही उसका पतन हुआ है।

महोदय, आज जब हम देश में कोरोनावायरस की चर्चा कर रहे हैं, अगर हमारा आयुर्वेद पहले जैसा एडवांस रहा होता, यानी प्राचीन काल जैसा होता, तो इस तरह के किसी भी वायरस में हमें कोई डर नहीं होता और न कोई भय होता, लेकिन आपने उसकी रिसर्च के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की। आपने इस संबंध में कमेटी की सिफारिश भी नहीं मानी।

महोदय, इसका जो एक क्लॉज 6(8) है, उसके बारे में कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, कमीशन के जो चेयरमैन हैं या जो मैम्बर्स हैं, उन्हें प्राइवेट मेडिकल एजूकेशन में एक्सपोर्ट के रूप में या कंसल्टेंट के रूप में मनोनीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट्स हो जाते हैं, लेकिन उसे भी overrule किया गया अर्थात् उस सिफारिश को भी स्वीकार नहीं किया गया।

महोदय, पूरी हेल्थ कमेटी ने सर्वसम्मति से अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए रिक्मेंड किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाए। अब ट्रिब्यूनल की बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करनी पड़ेगी, तो उससे कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

[प्रो. राम गोपाल यादव]

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि जो लोग पहले से हमारी दोनों की सेंट्रल कमेटीज थीं, उनमें काम कर रहे हैं, जैसे ही यह कमीशन बनेगा, उन्हें आप टर्मिनेट कर देंगे। मेरा कहना है कि आप इतने हृदयहीन मत बनिए और आपको मानवीय आधार पर उन्हें एडजेस्ट करना चाहिए, हमेशा एडजेस्ट किया जाता है। आपने न National Medical Commission वालों को एडजेस्ट किया और न इसमें आपने कोई सिफारिश मानी।

महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि तीनों बिलों में, NMC और दो ये, जिन पर हम अब चर्चा कर रहे हैं, इन तीनों में अधिकारियों ने कोई दिमाग नहीं लगाया। एक जैसे 58 Clauses हैं। इनमें केवल नाम बादल दिए गए और कमीशन के मैम्बरों की संख्या बदल दी गई। ऑलमोस्ट एक हैं। मेरा निवेदन है कि पुराने स्टाफ को रखिए।

महोदय, हमने सिफारिश की थी कि जैसे Governing Body, AIIMS की होती हैं, उनमें दो लोक सभा के और एक राज्य सभा का मैम्बर होता है। वैसे ही इन सबमें, जितनी भी यूनिवर्सिटीज और आयुर्वेद और होमियोपैथी के संस्थान हैं, उनमें दो लोक सभा के और एक राज्य सभा का मैम्बर होना चाहिए। वह सिफारिश भी आपने नहीं मानी। अभी कितने AIIMS हैं, उनमें कितने MP पहुंचते हैं? अगर ये संस्थाएं होतीं, तो जिनमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो कहीं न कहीं अधिकारियों को लगता है कि वे देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। उससे उनमें कुछ न कुछ सुधार होता है।

महोदय, यह तो बात हुई कि दोनों बिलों में जो कमेटी की महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं व नहीं मानीं, लेकिन मैं एक अन्य बात आपसे कहने जा रहा हूं कि हमारे जो आयुर्वेद और यूनानी सिद्धान्त हैं या होमियोपैथी है और खास तौर से मैं आयुर्वेद और युनानी सिस्टम्स के बारे में कहना चाहूंगा कि जब हम आयुर्वेद की चर्चा करते हैं, तो हमें पांच बातें याद रखनी चाहिए-एक अथर्ववेद की, एक चरक की, एक सुश्रुत की, जो शल्य चिकित्सा के थे, चरक मेडिसिन के थे, एक धन्वतंरि की, वे तो सुश्रुत के गुरु ही थे। पहले आश्रम में पढ़ते थे और जब निकलते थे और अच्छे वैद्य बनकर निकलते थे। वे नाड़ी देखकर बता देते थे कि क्या खाया, कैसा खाया और क्या गड़बड़ी है, वे यह भी नहीं पूछते थे कि आपको क्या कमी है या क्या बीमारी है, वे बहुत काबिल लोग हुआ करते थे। ऐसा इसलिए था, क्योंकि उनकी शिक्षा बहुत अच्छी थी। आप जो ये बिल ला रहे हैं, वह शिक्षा में सुधार करने तथा अच्छे वैद्य बनाने के लिए ला रहे हैं। उसमें बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है।

महोदय, जो नए आयुर्वेदिक कॉलेजेज खुल रहे हैं, वे हमने देखे हैं, उनमें जो पढ़ाने वाले हैं, वे सड़क पर चलने वाले एक मामूली आदमी के बराबर भी आयुर्वेद के बारे में नहीं जानते हैं, तो अच्छे वैद्य कहां से निकलेंगे? सर, यह बिल बहुत इम्पॉर्टेन्ट है क्योंकि

आज भी देश के गरीब लोगों का सबसे ज्यादा इलाज आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के जरिए होता है। देश के 75 फीसदी लोग बड़े-बड़े अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने की हैसियल नहीं रख सकते और न ही उनमें जा सकते हैं। अब तो इलाज भी इतना महंगा हो गया है कि सारे अस्पताल फाइव स्टार होटल्स बनते जा रहे हैं। वहां कौन-कौन जाएगा? पिछली बार हमारे एक सीनियर मिनिस्टर मेदांता में एक दिन चले गए थे। जब शाम तक कुछ टैस्ट वगैरह का 90 हज़ार रुपये का बिल बन गया, तो बिल देकर लौट आए कि अब नहीं कराएंगे। सर, अब ऐसा इलाज हो गया है। योग के जरिये बिना दवा के, बिना किसी खर्च के आदमी के मन, मस्तिष्क को और शरीर को दुरुस्त रखा जाता है। इससे इम्युनिटी इतनी बढ़ जाती है कि उसे कोई रोग प्रभावित नहीं कर सकता है। ...(**समय की घंटी**)... योग का मतलब ही यह है। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, आप इसका कुछ भी अर्थ लें, लेकिन योग का मतलब एडिशन होता है। वह मन, मस्तिष्क पर कोई जोर नहीं देता है और स्वास्थ्य को भी बढ़ाने का काम करता है। वह प्लस करता है, माइनस कुछ नहीं करता है। इसलिए इस योग और नेचुरोपैथी को, जिनमें एक पैसा खर्च नहीं होना है, इनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। अगर आपने बिल लाने का वादा किया है, तो बिल जल्दी लाइएगा या फिर इसमें बोर्ड को include कीजिएगा। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Please conclude, Prof. Yadav.

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।

श्रीमान, हमने अपने सारे पुराने धर्मग्रंथों, वेदों, उपनिषदों और अन्य स्रोतों में आयुर्वेद के बारे में जो पढ़ा है, सुना है, उनमें वे सभी यह बताते हैं कि कोई ऐसा रोग नहीं था, जिसका इलाज इसमें नहीं हो। सर, ऐसा कोई रोग नहीं था। आयुर्वेद ने, यूनानी दवाइयों ने मरते हुए व्यक्तियों को जिंदा करने का काम भी किया था। ये जो पैथीज़ हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है। पहले राजवैद्य होते थे, उनको राजा का, स्टेट का समर्थन प्राप्त होता था, इसलिए जब तक इस पैथी को स्टेट का समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक इसका विकास नहीं होगा।

महोदय, एलोपैथी ने सभी को खत्म कर दिया है। अगर अभी भी एलोपैथी के डॉक्टर से कुछ कहेंगे, तो वे यही कहेंगे कि इसका scientific validation नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इसके जरिये कम से कम यह तो कर रहे हैं कि यह भी एक विधा है, इसका भी एक कमीशन है और लोग इससे भी स्वस्थ हों। अगर अच्छे वैद्य होंगे, तो लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसका scientific validation कराने का अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। हम लोगों ने अधिकारियों से बार-बार पूछा है। ...(**समय की घंटी**)... इसका scientific validation क्यों नहीं करवा रहे

[प्रो. राम गोपाल यादव]

हैं? आप इसका scientific validation करवाइए और लोगों को सस्ता इलाज दिलाने की व्यवस्था की कीजिए, क्योंकि बड़े अस्पतालों में एलोपैथी के डॉक्टर्स के जरिए हिन्दुस्तान का गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता है। कुछ मामलों में होम्योपैथी रामबाण है और कुछ मामलों में आयुर्वेद भी रामबाण है। आपने मुझे यहां पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, as hon. Members have already submitted, this Bill has come out of a recommendation made by the Vice-Chairman, NITI Aayog in 2016. Replying to the queries put by the Committee, the Ministry had replied this. The question was: Why was it ineffective and why do you want to repeal the old Bill? The reply was that there was absence of effective provisions in the IMCC Act, relating to the constitution of council, membership, to have transparent selection of members and their tenure, no provision in the Act for taking action against colleges for non-compliance of standards, so on and so forth. Similarly, to another question they replied this. The question was: Why was it not effective? The reply was that there was lack of effective provisions in the Act to address the issues relating to membership, conditions for removal of members and president in the case of non-performance or otherwise, etc. Basically, the answer given was that the problem was structural in nature, that if the structural organisation of the Indian system of medicine is achieved, then the entire propagation and use of the Indian system of medicines by the citizens and people of this country would take place. Now, as we know, the new Bill, which has come up, largely addresses the structural issues in terms of increasing the number of members, three experts, etc. Several issues have been discussed by the hon. Members. But the basic question, which Prof. Ram Gopal Yadav just mentioned, is, why haven't or why hasn't it taken off? Whereas many of these practices and many of these medicines started in this country, why has it not taken off? To my mind, the most important thing is research. The lack of research in these branches of medicine has resulted in people not having enough confidence to adopt these medicines. Now, if you look at the objective of the National Institute for Indian System of Medicines, I find that there is an objective which says adoption of latest medical research but there is nothing after that in the Bill about research, conducting research, what kind of research to be carried out, whether the research has to be published, what kind of publication has to be done, what kind of scientific research would be done. Now, I would give you a suggestion, Sir. In Allopathy or in the clinical trials, what they follow largely all over the world is something called as randomized

control trials which has been now taken to different subjects. In the Indian system of medicine or in Homeopathy, no such approach, no such methodology is prescribed. Nowhere has it been captured. The people are unaware of it with the result that there is no confidence to adopt the practices. Unfortunately, the Bill does not address any such concern and there is nothing mentioned about research *per se* as to how to conduct a research, what the process would be.

The second point why it has not taken off, to my mind, is promotion. The promotion of Indian system of medicine and Homeopathy has not had backing of the Government at all. Even if there was a Bill, the allocations have not been much. It is only in the recent times and only in a few States that this has taken off whereas the kind of promotion that has been available to the allopathic branch of medicine, the so-called modern system of medicine, has not taken place. I think we have a lot to do in case of promotion.

Regarding the joint responsibility of the governing bodies and institutions to remove the misconceptions of people, nothing has been done about that. The information and education communication which could be provided free to people has not taken place. Various research bodies could be actually tagged together and jointly they could think about developing new research methodologies in these branches, it has not taken off. Health camps, which you find all the time, the so-called modern system of medicine, organizing that does not place. It is only rarely. We do not have T.V. shows. For example, as hon. Member, Prof. Ram Gopal Yadav was talking about, we do not have a first line of treatment except for Allopathy. We do not have any first line of treatment in the Indian system of medicine of Homeopathy. The same is to be developed, and I am not saying there is no potential. There is a lot of potential but develop research and scientific research, — I am not saying the process that is being adopted in Allopathy but you develop your own research methodology, your own research design and model — and then give it to the world. Now, unless that is done, an epidemiological kind of findings are there, we cannot have the first line of defence against diseases and epidemics. And if that happens, then, this kind of Indian system of medicine can actually take off. We do not have motivation. We have hospitals but they are not being monitored.

Now, another point, which is lacking in the Bill, is about the penalty. What is the penalty against quacks? What is the penalty against medical practitioners who are not registered and still practising? That is not mentioned.

[Dr. Amar Patnaik]

The next point, which I would like to mention, is about the appellate tribunal. The Government of India itself forms the committee, decides everything and also decides on the complaints. This is actually not a very happy situation. The States' representatives from the State Medical Councils do not find representation in the Central councils.

The last point, which I want to say again, Sir, is this. If you remember, my maiden speech in this House was on the Budget of the AYUSH Ministry when I had said that the philosophical underpinnings of all these four branches are completely different. It is not just different from Allopathy but it is different amongst the branches themselves. So, to club together three of the branches and only separate Homeopathy out, probably, would not give the final results that is expected. Thank you so much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Thank you for adhering to your time. Now, Shrimati Kahkashan Perween.

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, मैं 'The National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019' और 'The National Commission for Homoeopathy Bill, 2019' का समर्थन करती हूं। इनका समर्थन मैं इसलिए करती हूं कि इससे जो गरीब लोग हैं, उनको भी आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी में इलाज मिल सकेगा। इन बिल्स के माध्यम से कहीं न कहीं चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अभी प्रो. राम गोपाल जी ने जो बात कही, जो हमारी हेल्थ कमिटी के चेयरमैन भी हैं, मैं उसकी भी ताईद करती हूं। उन्होंने अपनी हेल्थ कमिटी के माध्यम से जितनी भी सिफारिशें रखी थीं, उनमें से बहुत सारी सिफारिशों को मंत्रालय ने माना है, लेकिन बहुत सारी सिफारिशें ऐसी भी हैं, जिन्हें क़ुबूल नहीं किया गया है। कल जब डा. विनय सहस्रबुद्धे भी अपनी बात रख रहे थे, तो वे चिकित्सा पद्धतियों में आधुनिकता की बात कह रहे थे। कहीं न कहीं एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को आज इतना ज्यादा बढ़ावा इसलिए मिल रहा है, क्योंकि वह आधुनिकता के दौर के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन वहीं हमारी बाकी की चिकित्सा पद्धतियां उसके सामरे कमजोर पड़ रही हैं। जब से यह हुक़ूमत आई है, तब से चाहे योग हो, आयुर्वेद हो, यूनानी चिकित्सा पद्धति हो या होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति हो, इन सबको बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। इसके लिए सरकार ने इनसे संबंधित दिवसों की घोषणा भी कर दी है। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, धनतेरस के दिन आयुर्वेद दिवस मानाया जाता है, 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जाता है, यह सब इसलिए किया जा रहा है, ताकि लोगों को इससे बेदार किया जा सके, इसके प्रति सजग किया जा सके।

महोदय, जहां तक इसके बजट की बात है, मैं डा. अमर पटनायक जी की बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक़ रखती हूं कि बजट में इसके लिए कम प्रोविज़न रखा गया है। इसे एक मामूली सी बात से समझिए कि अगर हम किसी छोटी सी दुकान से कोई साड़ी खरीदने जाते हैं, तो कीमत कम रहने पर भी हमें यक़ीन नहीं होता कि यह साड़ी अच्छी होगी या घटिया होगी, वहीं अगर सीपी की मार्केट में कोई दुकानदार किसी सस्ती साड़ी को महंगी करके भी बेच रहा होगा, तो उस पर हम ज्यादा यकीन रखेंगे, इसलिए मैं आपसे गुज़ारिश करूंगी कि इसमें जो बजट एलोकेशन दिया है, बजट का जो प्रोविज़न किया गया है, वह बहुत कम है। अगर हम इन चिकित्सा पद्धतियों को वास्तव में बढ़ावा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी इत्यादि चिकित्सा पद्धतियां आगे बढ़ें, तो इनके लिए बजट में ज्यादा प्रोविज़न करने की जरूरत है।

आख़िर में मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि योग और नेचुरोपैथी के लिए अलग से बोर्ड बनाया जाए। इसके लिए भी मैं हमारी हेल्थी कमिटी के चेयरमैन, प्रो. राम गोपाल यादव जी की बात की ताईद करती हूं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य इसकी बॉडी के भी सदस्य हों और इसके लिए मैं मांग करती हूं कि हमारी एक सिफारिश को जरूर माना जाए, बहुत-बहुत शुक्रिया।

†محترمہ کہکشاں پروین (بہار): میں 'The National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019' اور 'The National Commission for Homoeopathy Bill, 2019' کا سمرتھن کرتی ہوں۔ ان کا سمرتھن میں اس لئے کرتی ہوں کہ اس سے جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی آیوروید، ہومیوپیتھی اور یونانی میں علاج مل سکے گا۔ ان بلوں کے ذریعہ سے کہیں نہ کہیں چکتسا ویوستھا کو اور بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی پروفیسر رام گوپال جی نے جو بات کہی، جو ہماری ہیلتھ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، میں اس کی بھی تائید کرتی ہوں۔ انہوں نے اپنی ہیلتھ کمیٹی کے ذریعہ سے جتنی بھی سفارشیں رکھی تھیں، ان میں سے بہت ساری سفارشوں کو منسٹری نے مانا ہے، لیکن بہت ساری سفارشیں ایسی بھی ہیں، جنہیں قبول نہیں کیا گیا ہے۔ کل جب ڈاکٹر ونے سہاسرابدھے جی اپنی رکھ رہے تھے، تو وہ طریقہ علاج میں جدیدکاری کی بات کہہ رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں ایلوپیتھک طریقہ علاج کو آج اتنا زیادہ بڑھاوا اس لئے مل رہا ہے، کیوں کہ وہ جدیدکاری کے دور کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن وہیں ہماری باقی کے طریقہ علاج اس کے سامنے کمزور پڑ رہی ہیں۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے، تب سے چاہے یوگ ہو، آیوروید ہو، یونانی طریقہ علاج ہو یا ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہو، ان سب کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے لئے سرکار نے ان

†Transliteration in Urdu Script.

[श्रीमती कहकशां परवीन]

سے متعلق دِوَسوں کی گھوشنا بھی کردی ہے۔ آج ہم لوگ بین الاقوامی یوگا دِوس مناتے ہیں، دھنتیرس کے دن آیوروید دِوس منایا جاتا ہے، 11 فروری کو یونانی دوس منایا جاتا ہے، یہ سب اس لئے کیا جارہا ہے، تاکہ لوگوں کو اس سے بیدار کیا جاسکے، اس کے پرتی سجگ کیا جاسکے۔

مہودے، جہاں تک اس کے بجٹ کی بات ہے، میں ڈاکٹر امریتانک جی کی بات سے بلکل اتفاق رکھتی ہوں کہ بجٹ میں اس کے لئے بہت کم پروویژن رکھا گیا ہے۔ اسے ایک معمولی سی بات سے سمجھئے کہ اگر ہم کسی چھوٹی سی دکان سے کوئی ساڑی خریدنے جاتے ہیں، تو قیمت کم رہنے پر بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ ساری اچھی ہوگی یا گھٹیا ہوگی، وہیں اگر سی پی کی مارکیٹ میں کوئی دکاندار کسی سستی ساڑی کو مہنگی کرکے بھی بیچ رہا ہوگا، تو اس پر ہم زیادہ یقین رکھیں گے، اس لئے میں آپ سے گزارش کرونگی کہ اس میں جو بجٹ ایلوکیشن دیا ہے، بجت کا جو پروویژن کیا گیا ہے، وہ بہت کم ہے۔ اگر ہم ان طریقہ علاج کو حقیقت میں بڑھاوا دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آیوروید، ہومیوپیتھی، یونانی وغیرہ طریقہ علاج آگے بڑھیں، تو ان کے لئے بجٹ میں زیادہ پروویژن کرنے کی ضرورت ہے۔

آخر میں، میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ یوگ اور نیچروپیتھی کے لئے الگ سے بورڈ بنایا جائے۔ اس کے لئے بھی میں ہماری ہیلتھ کمیٹی کے چیئرمین، پروفیسر رام گوپال یادو جی کی بات کی تائید کرتی ہوں۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے سدسئے اس کی باڈی کے بھی سدسئے ہوں اور اس کے لئے میں مانگ کرتی ہوں کہ ہماری اس سفارش کو ضرور مانا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the National Commission for Indian System of Medicine Bill and the National Commission for Homoeopathy Bill. At the same time, there are so many limitations in the Bill. The Standing Committee chaired by Prof. Ram Gopal Yadav has made several recommendations. But, somehow, major recommendations are missing from the Bill. I would like to request the hon. Minister to please explain before going for the approval of the Bill as to how many recommendations have been considered; how many recommendations are included in the Bill; how many recommendations you have rejected and what are the reasons for that also. Sir, particularly, with regard to representation of the States, there should be more representation for the States. The representation of doctors is also only three in number. That should be increased to double in number because they are professionals and they can give valuable advice to the Government.

Another point is this. Sir, I want to bring it to the notice that here the Appellate Authority is only the Central Government. Instead of Central Government, the Appellate Authority should be an independent body so that they can function in a good manner.

Sir, another point is regarding the Advisory Council. There is no representation for the State medical colleges. I would request the hon. Minister to please consider the State medical colleges to be included in this Bill. Somehow, Yoga and Naturopathy are missing in this Bill. The Bill comes in the wake of rising demand to regulate the different traditional systems of medicine such as Ayurveda, Homeopathy, Unani, Siddha, Naturopathy and Yoga. The Bill, designed by the NITI Aayog, is modeled on the National Medical Commission Bill, 2017 and Naturopathy and Yoga should also be included. Why it is disappeared in the Bill, we do not know. The Parliamentary Committee has sought the inclusion of Yoga and Naturopathy in the National Commission for Indian System of Medicine Bill, stating these age-old practices with focus on holistic health are an integral part of Indian culture and the AYUSH system. The Committee also recommended that a Board of Yoga and Naturopathy be constituted under Clause 18 in the Bill. Currently, there is no central regulatory body for registration of Yoga and Naturopathy practitioners and standardization and recognition of 70 different courses of Yoga and Naturopathy. Almost 44 medical colleges affiliated to UGC, recognised universities offer Bachelor of Naturopathy and Yoga Science.

[Dr. Banda Prakash]

Registered as Yoga and Naturopathy medical practitioners in 15 States and Union Territories, there are over 10,000 students. Despite several representations from the organisations, the reasons not known, Yoga and Naturopathy are kept outside this Bill. Bachelor of Naturopathy and Yoga Sciences is a Medical Degree representing Yoga and Naturopathy system of medicine of the country, a fact which has been acknowledged and reiterated by the Ministry of AYUSH, Government of India in response to questions raised by hon. Members of Parliament on several occasions. Central Council of Indian Medicine, the current regulatory body covering Ayurveda, Unani, Siddha systems of Medicine, has on several occasions passed resolutions to bring Yoga and Naturopathy system of medicine under its purview. Fifteen States and Union Territories in the country are even conducting the programmes. In Naturopathy also, they are conducting post-graduate degree programmes in this country. Several universities are conducting this programme. The Government of India through an Executive Order tasked the work of Central Registration for Bachelor of Yoga and Natural Sciences medical graduates in 2017 to Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, an autonomous body under the Ministry of AYUSH. Yoga and Naturopathy has been an integral part of the Indian system of medicinal science since 1970. The Central Council for Research and Yoga, Naturopathy, was earlier under the Ministry of Health and Family Welfare and is now under the Ministry of AYUSH. Since 1989, India amalgamated Yoga with Naturopathy to develop a perfect blend of drugless, mind-body medicine and proven lifestyle intervention …

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Please conclude.

DR. BANDA PRAKASH: …by developing the medical education system through the first two colleges, which have been grown to 44 colleges in Yoga and Naturopathy. Our country propagates Yoga the most. It seems that our hon. Prime Minister is an international brand ambassador for Yoga. So, why is the Government excluding Yoga and Naturopathy from this Bill? I request the hon. Minister to answer this. At the same time, so many people in the rural areas, without any degree, without any qualification, are practising Yoga, Naturopathy and AYUSH medicine. A number of times, the people affected with Jaundice take medicinal leaves from the rural areas. Even there are so many doctors, bonesetters and others, who resolve all their medical problems. I request that any training for three-four months should be given to them

by doctors, RMP or PMP, and trained in this medicine and be given some certificate programme in that course.

THE VICE CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Shri Somaprasad. …*(Interruptions)*… Time is over. …*(Interruptions)*…

DR. BANDA PRAKASH: Sir, last point..…*(Interruptions)*… Sir, my last point. …*(Interruptions)*...*

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Shri Somaprasad, please speak. …*(Interruptions)*... Not going on record. Shri Somaprasad, please continue. Your clock is ticking.

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Sir, the modern medicine and the system of Indian medicine, especially, Ayurveda are two different streams of knowledge. Ayurveda is the oldest and comprehensive system of medicine being practised in India since ages. India has a very long history and a strong base of traditional medicine like Ayurveda. The strength of Ayurveda and other Indian system of medicine lies in their three-fold holistic approach of prevention of diseases, promotion of health and care of disease. Ayurveda could make a sufficient impact in the context of preventive medicine. Ayurveda gives utmost importance to the patient's safety during the treatment through rational use of medicines. Hopefully, even though it is not sufficient, in recent period, there are several research activities which are going on in the Indian system of medicines. But, the existing laws related to the various aspects of Indian system of medicine are not sufficient to meet various challenges that are being faced now. It is true that it is high time to enact a comprehensive law covering each and every aspect of education, research, practice, production of medicine, medical ethics, etc. The new legislation which we are enacting now is not comprehensive. But, it touches major issues related to Indian system of medicine. When we think about Indian system of medicine, we should not forget Naturopathy and Yoga. The Bill is silent about Naturopathy and Yoga. Yoga and Naturopathy are part and parcel of Indian system of medicine. Their demand is that these branches should be included in this Bill. It is their longstanding demand. That is a genuine demand. I would like to know about the intention of the Government. At present, in India, there are eight lakh medical practitioners who are working. Out of it, 55 per cent are ayurvedic doctors.

*Not recorded.

[Shri K. Somaprasad]

484 ISM colleges are spread across the 26 States in our country. The ayurvedic doctors are doing a commendable job in providing first line of treatment, especially, in rural areas. It is good that adequate representation has been given to them in this Bill. But, when we go through the Clauses, still there are certain defects which should be removed. Sub-Clause (7) of Clause 6 says, "The Chairperson or a Member, ceasing to hold office as such, shall not accept, for a period of two years from the date of demitting such office, any employment, in any capacity, including a consultant or an expert in any private medical institution of Indian system of medicine." ...*(Time bell ring)...* Sir, I need one more minute. The next sub-Clause 8 says, "Nothing in sub-section 7 shall prevent the Central Government from permitting the Chairperson or a Member to accept any employment in any capacity, including as a consultant or an expert, in any private medical institution." When sub-Clause (8) is in operation, then, what is the use of sub-Clause (7)? Knowingly, the Government is permitting malpractices and corruption. The gates are widely opened. The Chairman and members, all of them are nominated and they are all good boys of the Government. There will be no hurdle to get permission from the Central Government. What will be the net result? There is every chance for members to become the representatives of private medical colleges. There is every possibility not only for corruption but also for favouritism. Sir, like that... ...*(Time bell rings)...* there is another sub-Clause. Sir, I need one more minute. The duties of the Medical Assessment and Rating Board is explained in Clause 28. One of the major duties is to carry out inspections of medical institutions for assessing and rating such institutions in accordance with the regulations made under this Act. Who will conduct this assessment? As per the proviso, for and on behalf of the Autonomous Board, some private agency, a third party will do this job. The inspection and assessment will be outsourced. What would be the final outcome? We have the bitter experience of Indian Medical Council. If this duty is outsourced, the malpractice and bribery would become part and parcel of the assessment. I strongly oppose this proviso. It should be deleted.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Mr. Vice Chairman, Sir, DMK is opposing this Bill and requesting to send this Bill to a Select Committee. Sir, both the Bills are verbatim-same and are a mirror image. Sir, I find serious infirmities in this Bill. Clause 3 of the Bill takes away the participation of the professionals through Councils and

whoever was there in the decision-making process in the earlier Acts. Earlier, about 40 per cent of the professionals were there in the Council. Now this Council is renamed as a Commission. Now, it is going to be manned by the bureaucrats. The professionals who have put their heart, soul and life in fifty years of this Council, are now going to be hijacked by the bureaucrats. The professionals are going to be miniscule in number. The bureaucrats are going to kill the democratic system of professionals manning their own body. Sir, these bureaucrats, who are going to be the outsiders, can they man this professional body? So, we would request the Minister to please restore the Council with elected professionals, and let the professionals to man this Council. Sir, the new Bill tries to divide the society. Sir, Clause 4 (4)(a) and Clause 5 (1)(d) are trying to create a barrier among the persons who are going to be selected as a part-time professors as well as in the Select Committee. The persons who know Sanskrit language only for part-time professors and to be in Selection Committee, are going to be selected. Sir, why language is a barrier there? If so, why don't you make Tamil as one of the languages? Now, we are putting a person knowing Sanskrit in high pedestal to be selected than the persons knowing other languages. Therefore, Sir, this Clause 4 (4)(a) and Clause 5 (1)(d) are highly discriminatory, violative of Article 14 and violative of Article 16 of the Constitution. Sir, equality before law should be applied and equal opportunity should be given to all of them, that is what Article 16 says. Now, I do not know as to why you include Sanskrit language as a qualification to the post of part-time lecture and member of Select Committee. Therefore, there is a discrimination between the person who knows Sanskrit language and who do not know Sanskrit. Sir, Siddha is a unique system of medicine in Tamil Nadu. It can be traced back to the Siddhar period. The Siddhas have written this in Tamil language. So, why did you leave Tamil language while selecting persons who are well familiar with Siddha? Sir, one more important thing is that the Bill tries to discriminate Yoga and Naturopathy. Sir, our former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, he floated AYUSH and he recognized Naturopathy and Yoga as one of the systems of medicine. It was there for about seventy years. Now, fifteen States in India regulate Yoga and Naturopathy through their executive orders. When the draft Bill was introduced by the NITI Aayog, it has clearly recommended for Yoga and Naturopathy. Now, when the Bill is introduced Yoga and Naturopathy are deleted. Sir, the Standing Committee recommended for inclusion of Yoga and Naturopathy. Yoga is taken to the whole world, as my previous speaker said, by the Prime Minister. Why are you forgetting Yoga

[Shri P. Wilson]

and Naturopathy? In Naturopathy, you can see natural way of healing. Yoga therapy, acupuncture, acupressure, magnetic therapy, mud therapy and hydro therapy, these all are the methods of curing the disease. ...*(Time bell rings)*... Now, you want to leave Yoga and Naturopathy. Sir, I would say that nearly 1,000 professionals are there, 42 colleges are there in India and ten colleges are there in Tamil Nadu imparting education on Yoga and Naturopathy.

Why do you have this NEET and NEXT examinations, and, NEET again, in the Post graduate course also? Sir, a uniform system of school education is not available throughout India. Every State has got their own system of education. Therefore, where is the question of having a level-playing field? This common NEET examination is going to cause a disaster. It has already caused disaster so far as the MBBS admission is concerned. Sir, I would say this common NEET is not at all required because each State has their own system of education. Sir, so far as the NEXT examination is concerned, why do you have another final examination when they have already passed the final exams, when the university has conducted the examination and given a degree? Why do you have another examination again in the form of NEXT? Sir, so far as the Post Graduate admission is concerned, you have the marks, you have the grades, why do you have another examination for Post Graduation? Therefore, Sir, I would request that let the 2 bills be sent to a Select Committee. You are trying to divide the people using language and caste. Please do not do it. Thank you, Sir.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Thank you Mr. Vice Chairman, Sir, for giving me this opportunity. This Bill would bring two important reforms. Firstly, it enables transparency and accountability and secondly it creates further trust on the Indian Medical Sciences. Sir, this Bill, if adopted, would establish two National Commissions, and these two Commissions, to promote the availability of affordable healthcare services and to streamline the functions related to academic standards, evaluation, assessment, and accreditation of educational institutions. Therefore, it is very important, and I, on behalf of my Party, stand to support this Bill. Sir, this Bill addresses two bottlenecks in the functioning of the present Council. This Bill also addresses the issue of supply of doctors as it promotes equity by ensuring adequate supply of quality medical professionals, and secondly, enforces high ethical standards. Sir, I have a few suggestions to be made to the hon. Minister. Many Members in

the House, particularly from the Opposition side, have raised the issue of non inclusion of Yoga and Naturopathy, and, in fact, 115th Report of the Departmental-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare has specifically stated that these two are important, and they are to be included in this Bill. However, they are excluded. It is very unfortunate, and I request the hon. Minister to include these two also in the Bill. Sir, if Yoga and Naturopathy are left unregulated, then, the system of medicine cannot have uniform professional standards and accreditation process. Therefore, posing an impediment is not at par with the other Indian Systems, such as Ayurveda, Homoeopathy, and Unani, Sir.

Sir, I draw your attention to Clause 11, Sub-Clause 2(C) of the NCISM Bill which says, 'This may result in disproportionate representation of various branches, what have been referred to in the Bill.' Sir, therefore, instead of State-wise representation, the State-wise representation may be converted into subject-wise representation from each of the State so that each branch of medicine is proportionately represented from that State or Union Territory.

Lastly, there is a need to address quackery most effectively. I draw your attention to Clause 33, Sub Clause 1 of NCISM which dilutes the entire system that is being created. Your attention is drawn to Clause 33. I am reading in verbatim. "No person, other than a person, who is enrolled in the State Register or the National Register, as the case may be, shall practice.'' Now, there is a proviso to that. In the proviso, it is stated: " Provided that the Commission may permit a qualified person to practice in Indian System of Medicine without qualifying the National Exit Test, in such circumstances, for such period, as may be specified by Regulations.'' This dilutes the very objective of the provision. I, therefore, draw the attention of the hon. Minister to plug this loophole and we stand to support this Bill. Thank you very much.

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज यहां इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिंस और होम्योपैथी के संदर्भ में जो दो विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए आपके समक्ष प्रतिवेदन दे रहा हूं। अभी जितने भी हमारे सम्मानित वक्ताओं ने बोला, प्रो. राम गोपाल यादव जी ने, अमर पटनायक जी ने और साथ ही अन्य कई वक्ताओं ने भी इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया कि यदि रिसर्च, promotion और standardization, यानी अनुसंधान, प्रसार और मानकीकरण हो गया होता या बेहतर ढंग से हम इन चीज़ों को प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। उनके concerns बिल्कुल उचित थे, परंतु मेरे विचार से ये चीज़ें आज तक इसलिए नहीं हो पाईं, क्योंकि व्यवस्थित प्रभावी उपकरण,

[डा. सुधांशु त्रिवेदी]

यानी जो एक effective mechanism चाहिए था, वह अभी तक उपलब्ध नहीं था। सरकार ने इन बिलों के माध्यम से इस प्रकार का एक प्रभावी उपकरण बनाने का प्रयास किया है, जिसके द्वारा हम रिसर्च, standardization और इन चीज़ों को आगे स्थापित कर सकेंगे। अब मैं एक और बात यह कहना चाहूंगा कि हम यह बात करते हैं कि आज इसकी आवश्यकता क्या है? उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मैं टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी हूं और मैंने यह देखा है कि पोलिटिक्स और टैक्नोलॉजी में यह संबंध है कि आप टेक्नोलॉजी का paradigm बदल दीजिए, पावर का paradigm बदल जाता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही अमेरिका के पास एटम बम आया, पावर paradigm यूरोप से शिफ्ट होकर अमेरिका चला गया। आज यदि हम फार्मास्यूटिकल्स और मेडिसिंस के क्षेत्र में देखें, तो पश्चिमी देशों ने इतनी प्रगति कर रखी है कि यदि हम उसी branch of knowledge में उनके फॉलोअर बनना चाहेंगे, तो जैसे अमेरिका के Food and Drug Administration (FDA) ने — तो हमें उनके आस-पास पहुंचने में दशक लग जाएंगे। परन्तु, यदि हम paradigm shift कर दें, तो वह paradigm shift alternative sources of medicine है, जिसमें होम्योपैथी और आयुर्वेद आते हैं, जिनके पस यह आधार है, जिनका मूल आधार ही उन चिकित्सा पद्धतियों से अलग है। यदि हमने इसमें अपने को सही ढंग से स्थापित कर लिया, तो हमें 80 से 90 प्रतिशत मामलों में उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो वे हमें बड़े ऊंचे मूल्यों पर देते हैं।

मैं सिर्फ एक बिन्दु की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि किस मामले में हमारे इंडियन सिस्टम और उनके सिस्टम की मूल प्रकृति अलग है। देखिए, जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, वे सब चिकित्सा विज्ञान हैं। आप उनसे पूछिए कि व्यक्ति स्वस्थ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अगर उसको कोई रोग नहीं है, तो वह स्वस्थ है। अगर उसे कोई रोग हो जाएगा, तो उसे उस रोग की दवा दे देंगे। परन्तु, बात यह है कि by name itself, आयुर्वेद आयु का विज्ञान है। यहां पर ऐसी भी औषधियां उपलब्ध हैं, जो आयु के संरक्षण और संवर्धन के लिए उपयुक्त हैं और प्रभावी हैं। इसीलिए आप देखें कि बाकी जो western medicinal thoughts हैं, वे यह क्लेम ही नहीं करते कि general immunity को बढ़ाने के लिए उनके पास सिवाय multi-vitamins and multi-minerals देने के बहुत कुछ है। हम देख भी रहे हैं कि जिस प्रकार virus and immunology related खरते बढ़ रहे हैं, अगर हम इसे प्रभावी ढंग से रख पाएं, तो समझिए यह आयु का विज्ञान, आयु के संरक्षण और संवर्धन में एक प्रभावी रोल प्ले कर सकता है।

अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग यह कहते थे कि साहब, हमें उसके हिसाब से साइंटिफिक ढंग से इन चीज़ों को आगे रखना चाहिए। अब किसे साइंटिफिक कहें, उपसभाध्यक्ष महोदय? केवल 40-50 साल पहले की ही तो बात है जब यह कहा जाता

था कि यह फूल-पत्ती खाकर क्या कोई इलाज होता है? क्रोसीन, टेरामाइसिन, मेटासिन खाओ, आधुनिक बनो, नई-नई मेडिसिंस खाओ। आज 50 साल के अंदर हम फिर यह कहने की स्थिति में आ गए हैं कि go back to herbal medicine. भाई, साइंस तब सही थी या अब सही है? हम तो तब भी वही थे, आज भी वही हैं, आप बदल गए हैं। इस बदलाव को अब हमें विश्व को स्वीकार करवाने की आवश्यकता है बजाय इसके कि हम उनके हिसाब से अपनी व्याख्या करने का प्रयास करें।

अब मैं एक अन्य उदाहरण आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। जैसा कि हमारे कई सम्मानित वक्ताओं ने औषधियों के बारे में बताया। चरक से लेकर धन्वन्तरि जी तक ऐसे बहुत-से उदाहरण उपलब्ध हैं, परन्तु जिसको वैस्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है, वह है सर्जरी। सर्जरी की जितनी डिटेल्ड जानकारी आयुर्वेद में उपलब्ध है, उतनी कहीं और नहीं है। सुश्रुत संहिता में 180 चैप्टर्स हैं, 1,100 डिजिज़ेज हैं, 121 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 650 मेडिसिंस हैं, जिनमें animal, plant and metals, ये सभी सोर्सेस से हैं और 300 से ऊपर प्रोजीजर्स हैं। इतना ही नहीं, शायद कुछ लोगों को सुनने में अटपटा लगे, परन्तु हड़प्पा सिविलाइज़ेशन, जिसे आज हम सिन्धु-सारस्वत सभ्यता कहते हैं, उसके excavation करने वाले सर जॉन मार्शल, जो ब्रिटिश टाइम में ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे, उन्होंने अपनी बुक, जिसमें उन्होंने तक्षशिला के excavation का जिक्र किया है, उसके पेज नम्बर 210 पर लिखा है कि surgical instruments of Indian Civilization second century से अवेलेबल हैं। आज भी अगर आप पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के म्यूज़ियम में जाइए, तो पाएंगे कि वहां दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के surgical instruments रखे हैं। जब वहां पूर्व लोक सभा अध्यक्ष, मीरा कुमार जी गई थीं, तो वर्ष 2012 में उनके अख़बारों ने इसको रिपोर्ट भी किया था। मैं केवल यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि surgery, जिसको बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाता है, वह बहुत पुरानी पद्धति है।

सर, उसके संबंध में एक और तथ्य मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। लोग प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात करते हैं। लंदन से निकलने वाली एक बड़ी फेमस मैगज़ीन, जिसका नाम The Gentleman था, उसमें वर्ष 1794 में दो डॉक्टर्स, टॉम्स क्रूसो और जेम्स फेंडिल ने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा। यह लंदन में छपी हुई मैगज़ीन है और 1794 में वे लिख रहे हैं कि भारत के पुणे में 1793 में एक व्यक्ति की नाक कट गई थी। उस नाक को जोड़ने की प्रक्रिया आयुर्वेदिक सिस्टम से उन्होंने देखी and that was successfully done. यह उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया। मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने यह लिखा कि पुणे में जो नाक जोड़ने वाले थे, वे कौन लोग थे, वे कोई बहुत पढ़े-लिखे, हाई क्लास के नहीं थे। उन्होंने लिखा कि वे कुम्हार जाति के व्यक्ति थे, जो आज की तारीख में ओबीसी में आते हैं। यह दर्शाता है कि जो हमारा advance source of knowledge था, हम कहीं न कहीं, किसी न किसी कारण से उसे पीछे छोड़ते चले गए।

[डा. सुधांशु त्रिवेदी]

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद कोई separate subject नहीं था, जिसको वे मेडिसिन साइंस से रिलेट करते हैं। जैसे हमारे यहां Zoology, बॉटनी, केमिस्ट्री एक sequence है, फ़िजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथ्स, एक सब्जेक्ट का ग्रुप है, वैसे ही तीन सब्जेक्ट्स के ग्रुप में से एक आयुर्वेद था, जो बड़ा व्यवस्थित branch of knowledge था, वह था कृषि, पाक-शास्त्र और आयुर्वेद। कृषि means how to grow, पाक-शास्त्र means how to cook and आयुर्वेद means how to get the medicinal value. उन सारी values को हम अच्छी तरीके से समझें और यदि हम उन चीज़ों को समझ पाएं तो आज हमें एक और चीज़ में बहुत लाभ मिलेगा, यह जो structured mechanism सरकार लायी है। आज intellectual property को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, यदि आयुर्वेद के ग्रन्थ हमारे प्रभावी स्थिति में थे, उन्होंने हमें नीम के पेटेन्ट से, हल्दी के पेटेन्ट से, तुलसी के patent से मदद की, किन्तु आज तक भारत सिर्फ प्रतिक्रियात्मक रहा कि जब दूसरे ने patent कराया, तब हम जाकर खड़े हुए और कहा कि यह हमारा है। यदि यह जो प्रभावी mechanism सरकार ने बनाया है, इसके द्वारा हम अब pro-active होकर कह सकते हैं कि ये सारे पेटेन्ट्स हमारे हैं तो trade-related intellectual property में भी आप समझ लीजिए कि इसका एक हमें बहुत अच्छा लाभ फ्यूचर में मिलने वाला है।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत सी देसी दवाएं हैं, जिनकी तरफ यदि हम ध्यान दें, यदि हम केवल उनका साइंटिफ़िक नाम पढ़ लें तो हमें बहुत कुछ आसानी से समझ में आ जाता है, जैसे हृदय के लिए अर्जुन का पेड़ होता है। आपने अर्जुनारिष्ट और अर्जुनासव सुना होगा। यदि आपने केवल उसकी बोतल देखी हो तो उसकी बोतल पर उसका साइंटिफ़िक नाम Terminalia Arjuna लिखा है। वह heart के लिए proven है and the name is Terminalia Arjuna. यह अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि जो हम कह रहे थे... अब छोटी सी बात यह कि कॉमन भाषा में तुलसी के लिए Holy Basil शब्द प्रयोग होता है, holy शब्द तो अंग्रेज़ी ने दिया है, हमने नहीं दिया है, फिर भी कहीं न कहीं यह स्वीकारोक्ति है कि इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है। उदाहरण के लिए जिन-जिन वनस्पतियों को हमारे यहां स्वास्थ्य की दृष्टि से और पूजा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया, जैसे पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष को holy fig कहते हैं, मगर उसका साइंटिफ़िक नाम Ficus Religiosa है। महोदय, उसमें religion है। वह उसमें Ficus Religiosa बता रहा है यानी ये मान रहे हैं कि यह धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाने वाला जो पड़े है, इसके अंदर बहुत सारे medicinal गुण हैं। अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि देखिए इसमें गर्व करने की आवश्यकता है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि यह आयु का विज्ञान है, कल विनय पी. सहस्रबुद्धे जी ने जब इस विषय पर अपनी बात रखी थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि गर्व से कहो कि हम हैं, वह किसी दूसरी चीज़ के लिए कहा था, आप वह मत

कहिए, क्योंकि जब कहा जाए कि गर्व से कहो हिन्दू हैं, वह ठीक नहीं लगता, इसलिए गर्व से कहो हम हैं। मगर मैं कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद अथर्ववेद का हिस्सा है and Veda is a religious text. Nowhere in the world can you find medical science as part of religious text. Nowhere can you find mathematics as part of religious text. इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह जो हमारा ज्ञान है, यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, गरीबों के लिए ही नहीं, बल्कि सबसे advanced level पर जो लोग बैठे हैं, उनके लिए भी उतना ही प्रभावी है और यह पूरे विश्व को आगे ले जाने की क्षमता रखता है। जो Australian College of Surgeons हैं, उन्होंने Sushruta को सर्जरी का जनक माना है Melbourne में, अमेरिका में क्या माना जा रहा है, वह सबको पता है। मैं यह पंक्ति कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, जो अटल जी ने कहा था,

"मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर।
मानव के मन का अंधकार, क्या कभी सामने सका ठहर?
मेरा स्वर नभ में घहर-घहर, सागर के जल में छहर-छहर।
इस कोने से उस कोने तक, कर सकता जगती सौरभमय।"

आगे मैं विनम्रता के साथ कहूंगा कि

"हिन्दू तन-मन, हिन्दू जीवन, रग-रग हिन्दू मेरा परिचय!"

महोदय, यही जीवनशैली है, धन्यवाद।

SHRI OSCAR FERNANDES (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I stand in support of these Bills. However, I have received a number of representations from people in the field of Naturopathy and Yoga saying that they have been left out from the purview of the National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019. Ram Gopalji had mentioned that the Standing Committee on Health and Family Welfare recommended that Naturopathy and Yoga also be included in this Bill. I would like to urge the hon. Minister either to amend this Bill or give an assurance to this House that he would bring a separate legislation to cover Yoga and Naturopathy.

We are aware that in a number of States — as many as fifteen States — more than 40 institutions are teaching Yoga and Naturopathy. Now, we are talking of reaching out to every citizen in this country to provide him medical care. Our own Indian System of Medicine will provide a lot of relief even before going to a doctor. As a village boy — I had been a farmer — working in a village, I had an opportunity to look at various herbs. My esteemed friend, Mr. Jairam Ramesh, pulls my leg when I talk of *gomutra*. I had been to an ashram near Meerut and it was late in the night

3.00 P.M.

[Shri Oscar Fernandes]

when I reached there. I talked to swamiji there. And, I had to reach back to Meerut and I did not know the route. So, swamyji was kind enough to lend his driver to show me the path. As I was discussing with the driver, I asked him, 'Why are you here?' He said, 'Sir, I had cancer. I was suffering from serious cancer. There was no treatment which could cure me. Ultimately, I came to this ashram. In this ashram, I got relief from *gomutra* and my cancer was cured. And, I have decided to serve this ashram for the rest of my life and will not take up any job, because this ashram has given me a new lease of life.'

Let me explain one more experience of mine. I said that I was in a village doing cultivation. When I got elected to Parliament, I had to choose either to work in Parliament or to be a farmer. And, I had no option but to give up farming. When I had given up farming, I had a severe pain in knee joint. When I went to get it examined, a doctor told me, 'You need replacement of your knee joints.' I said, 'Doctor, short of this, tell me anything, I will do. But, I cannot go for knee replacement.' Then he said, 'You strengthen your muscles.' I said, 'Okay.' I was not able to climb the stairs. I started Vajrasan and practicing Yoga. Today, I am able to boldly tell you that I could do even wrestling without any difficulty. When hon. Prime Minister, Shri Vajpayee, had a knee surgery, I thought if I had known it earlier, I would have definitely gone to Pradhan Mantriji and asked him to follow Vajrasan and he could have been cured without difficulty. Doctors told me that there is no question of recovery of pain there, it is worn out and it cannot be cured. But, with Vajrasan, today, my knee joints have been cured.

Sir, I had an opportunity to visit the USA a decade ago. I had a chance of interacting with several Indians over there.

I met a very elderly person. On meeting him, I wished him. He asked, "फर्नांडिस जी, बताइए कि मेरी उम्र कितनी है?" I got surprised. I said, Sir, "मैं नहीं बता सकता हूं। हो सकता है कि आपकी उम्र 70 साल है।" उन्होंने कहा, "नहीं।" Then, I asked him, "क्या 80 साल है?" उन्होंने कहा, "नहीं।" Then, I said, "सर, मैं नहीं बता सकता हूं। आप ही बता दीजिए।" उन्होंने कहा, "मेरी उम्र 104 साल है।" मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, "मैं योगा करता हूं; I teach Yoga; I practise Yoga." And, at the age of

104 years, he was able to move like a young man! Yoga is our wealth. If you practise Yoga, maybe our budget on health care may be reduced by more than fifty per cent. It's a way of life. Coming to Naturopathy, my own wife goes to a Naturopathy centre in my district Darmasthala. She regularly goes there twice a year for 10 to 20 days and practices naturopathy. I have been to that centre. There is a beautiful naturopathy college. A number of children are being educated to be doctors and they, in turn, go for teaching Yoga and Naturopathy. A number of Members have spoken today on Naturopathy and Yoga. And, this is a must. In my own home, my maid had abscess. She was suffering and crying like anything. Though she was taking medicine, but that was not effective. So, I just asked her, "थोड़ी हल्दी ले लो and apply it with coconut oil. इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा।" After three days, I asked her, "Did you go for operation?" I forgot to tell here that doctors had advised her for operation. She said, "नहीं, मेरा दर्द खत्म हो गया है।" So, nothing, but turmeric and coconut oil provided her relief. There are so many instances. One day, I was planning to come to Delhi. *(Time-Bell-rings)* On the way, I met a worker. He told me that he was going to Manipal Hospital. I asked him why he was going there. He told me that his leg was going to be amputated. I asked him when it was going to be amputated. He said, "After a week." I said, "This way, your situation will deteriorate. What you are going to do?" He said, "I don't know, Sir, what to do." Then, I said, You take *sadabahar*, you will get some relief." He agreed to that. When I returned after the Parliament Session was over, I had a chance to meet him. I asked, "What happened, amputation नहीं हुआ?" He said, "मेरी बीमारी खत्म हो गई है।" He got cured with an ordinary life of *sadabhar*. He was saved of amputation! I can narrate the experiences of my whole life. But, I think, I don't have enough time as you have already rung the Bell. So, I would like to put an end to my speech here. I request the hon. Minister to kindly consider about Ayurveda and Yoga. Thank you very much.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, these two Bills are positive steps, provided the Government considers the positive aspect of the Bills and the possibilities of these. And, those possibilities are to make those two, three, four, or, five areas of medical system foolproof. There, at present, quacks are ruling, bribes are ruling, and money is the practice, corruption is rampant. Corruption was very rampant. For a change, if the Government uses these Bills, it is positive. In that way, one will welcome that. But, the Indian system of medicines, mainly Ayurveda and Yoga itself, all of them have positive roots and they are scientific also. Forgetting science completely and

[Shri Binoy Viswam]

going behind superstitions will not help any system of medicine. An argument is now prevailing in the country that for everything including corona or cancer, cow dung or cow urine is the panacea. It is nothing but superstition, blindness and absolute disregard for science. Treat the medical systems of India as a scientific one, not as a primitive one and not as a matter to be considered only with the eyes of superstitions. There are tendencies in the country including from those of the Government to treat all these systems as part of the superstitions. This is my first point. So, if the Government takes the positive possibility and prospects of these Bills, it is good for the country. Naturopathy is also a part of the Indian system of medicines, but that is forgotten by the Governments. Please take ample consideration to also include the concerns of Naturopathy in the parameters of these Bills. When this becomes an Act, that is a must. It would also have its curative significance and impact on the country. That is also very important. While choosing the members to the commission, what should be the criterion? The criteria, of course, should not be money. It should not be political influence also. In the past, it was like that, either money or political clouts, or nearness to the people at power. That was the criterion. That has to be changed. Their knowledge in the subjects, their practice and the history of their practice should be taken into account. Such kind of people who are really meant for these treatments and its education and propagation, they should be considered for the commission membership. In a way, Rajya Sabha itself is becoming a place for people who are saying yes to the Governments; we are seeing it. Till the last six months back, a scar on the face of the Judiciary was such kind of nominations. But, now, all of a sudden, such kind of people are coming in as nominated and well dignified and *bona fide* Members. That should not be the practice. The Government may have some interest of politics and may have some friends. They may have something to do for them, for their service for the cause of the Government. But any commission, any committee, any membership of Rajya Sabha or Lok Sabha, anywhere it is, should not be the place for recruiting and pushing in such kind of people. While we make the suggestion for the commission membership, please see that only one thing should be considered, that is, their knowledge of subjects, expertise, experience and their scientific approach to the issues. Then only this commission can be of use for the country and for the people. With these words, I support the Bill. Thank you.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, let me say that it was wonderful to hear the personal experience of Oscar Fernandes*ji*. I am sure it is the use and practice of all the Indian systems of medicine that has brought him back hale and hearty to the House. Touch wood and wish him the best of health. Sir, I stand here to support the National Commission for the Indian Systems of Medicine Bill and the National Commission for Homoeopathy Bill, which repeals the earlier Acts. The objectives are certainly laudable because it tries to streamline the streams of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy. It ensures availability of adequate and high quality of medical professionals, the adoption of latest research work, periodic assessment of institutes and an effective grievance redressal mechanism, which is absolutely important, and, probably, was lacking in the earlier Bills. There have been some lacunae which have been pointed out by my colleagues earlier, I will not point out to that because of the paucity of time. I will only seek one clarification under each Bill. Sir, the first one is that the Bill, that is, the National Commission for Indian System of Medicine surprisingly does not include Yoga and Naturopathy, which a lot of my colleagues have already said, within its ambit. Sir, there have been demands for including Yoga and Naturopathy from several quarters. We fail to understand why it has not happened. In fact, the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare noted in its Report and it specially says that both systems have been excluded without sufficient reason. There are Paras in the Report 4.15.6, 4.15.7, 4.15.8, and I summarize what it says, “Yoga is now practised world-wide.” Thanks to our hon. Prime Minister that it has been acclaimed all over the world, all along the globe. It is considered as a panacea for a meaningful life and living. Sir, without any regulatory measures, poor-standard institutes run by unqualified practitioners will remain unchecked, and, therefore, there was absolute necessity that Yoga and Naturopathy should have been included in this Bill.

Sir, secondly, under the National Commission for Homoeopathy Bill, I seek clarification even on this point. Sir, Clause 52 of the Bill says, “Every State Government, may, for the purpose of addressing and promoting healthcare in rural areas take necessary measures to enhance the capacity of healthcare professionals.” Sir, this provision is insufficient to address a very, very long pending demand that the Ayush practitioners should be integrated with the mainstream. Sir, here we see that considering the large portion of Indian population which lacks healthcare services due to acute

[Shrimati Vandana Chavan]

shortage of MBBS doctors, considering that the National Health Policy of 2017, National AYUSH Policy and many Government Committees have recommended that the need of modern medicine, training and allowing them to practice modern medicine should be extended to the AYUSH doctors or Ayush practitioners which is to the tune of 7,70,000, this will take care of the shortage of healthcare human resources. Sir, this was absolutely a golden opportunity to give access to the AYUSH practitioners, maybe, in a limited way, to be included under Clause 52 with a specific recommendation. Though it has not been done here, I suggest to the Government that it should be included in the Rules so as to make it easier for the AYUSH practitioners to reach out to all those people in the rural areas and the poor population of our country to receive healthcare services. Thank you, Sir.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Thank you, hon. Vice-Chairman, Sir, for giving me the opportunity.

My first request, through you, to the hon. Minister *Sahib* is, if you look at both the Bills and also recall the NMC Act, which was passed in the last Session, verbatim, the back-side of the Bills matches. I think, it is a very poor 'copy and paste' job. I urge this, I feel bad. It is not your fault but the team which works with you has to take these issues into cognizance. This is number one.

Number two, Sir, I want to make my complaint very clear. दो बिल हम एक साथ चला रहे हैं। अगर ये एक जैसे ही थे, तो अलग-अलग बिल की जरूरत नहीं थी। मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया और पद्धति को हमें दरकिनार करना चाहिए। कल को जब इतिहास पढ़ा जाएगा, तो कहा जाएगा कि देखिए, दो बिलों को एक साथ चर्चा में लाया गया। बहरहाल, कल रात मैं बैठा, तो मैंने भी टेबुलर अरेंजमेंट करने की कोशिश की कि मैं भी एक ही साथ दोनों बिलों को रखूं। थोड़ी देर बाद मैं थक गया, क्योंकि मुझे लगा कि दोनों बिलों के चरित्र में कुछ अंतर है।

महोदय, हमारे सीनियर साथी, प्रो. राम गोपाल यादव जी यहां बैठे हुए हैं। अब सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, अब खिलौने भी बिना चाबी के नहीं चलते। आपको कमेटी की ओर से काफी चाबियां मिली थीं, लेकिन आपने उन्हें क्यों दरकिनार किया? इसका कोई rationale नहीं है। आयुर्वेद की क्षेत्रीय विविधता है। उन विविधताओं को संज्ञान में न लेकर के, दरकिनार करना, मैं नहीं समझता कि कहीं से भी यह तर्कसंगत है या justify किया जा सकता है। फिर strength of members in Search Committee की बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा

कि आप इसको संज्ञान में लें। Yoga and Naturopathy के बारे में तमाम सदस्यों ने कहा है। मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपकी ये बेरुखी शायद हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी को भी अच्छी न लगे, इसलिए हमारा नहीं तो उनका ही ख्याल कर लीजिए और Yoga and Naturopathy को इस दायरे में ले जाइए। Clauses 6, 7 and 6(viii) regarding Government's position that permission of the Central Government, Chairperson and members consultant का काम ले सकते हैं।

[**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कहकशां परवीन)** *पीठासीन हुईं*]

सर, आप यह discretion अपने आप मत रखिए। एक तरफ तो आप चीज़ों को privatize कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहां चाहते हैं कि सारी शक्तियां आप ही के पास हों। यह discretion biased है और इसमें favouratism की बू आती है। माननीय मंत्री महोदय, मैं जानता हूं कि ऐसी बू आपको भी अच्छी नहीं लगेगी।

Sir, 'Board of Research', Clause 18 में भी, जिससे multi-disciplinary research promote होता, आपने वह भी नहीं किया। Talking about the NCISM, the Ministry has also not accepted, the recommendation of the Committee regarding the constitution of an appellate tribunal. सर, यह होम्योपैथी बिल में भी एप्लाई होता है। यह मामला दोनों में ही है। यह आपके cooperative federalism, जिसको हम बार-बार यूज़ करते हैं, उसके नज़रिये से भी उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि स्टेट्स के साथ जो separation of powers है, यह उसके संदर्भ में भी उचित नहीं है।

सर, मैं क्लॉज़ 57(3) पर भी कहूंगा। एक तो वैसे ही बेरोजगारी का आलम बहुत भयावह है, कोहराम मच रहा है और दूसरी तरफ आप लोगों को नौकरियों से बर्खास्त कर रहे हैं। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप उनको कहीं समायोजित कीजिए। आप बोर्ड में, कहीं भी, कोई भी कोई चीज बनाएं, उनको उसमें रखिए। माननीय मंत्री महोदय, आपको उनके मद्देनजर कुछ सोचना होगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट और लूंगा। होम्योपैथी वाले में कमेटी की जो एक recommendation थी, for three Members of Parliament, I think you should readily take that into account. This is another suggestion of mine. Sir, talking about NCISM, regarding the regulation of paramedical courses, उसमें भी आपकी चुप्पी समझ में नहीं आ रही है। माननीय मंत्री महोदय, ये सारे सुझाव, जे हमने आपके सामने रखे हैं, उनका आशय यह कतई नहीं है कि मैं इस बिल के समर्थन में नहीं हूं, मैं इस बिल के पक्ष में हूं, लेकिन कोई भी चीज आधी-अधूरी नहीं होनी चाहिए। सदन में कई चीज़ों का ज्ञान मिलता है। मेरे एक मित्र ने अभी कहा कि अथर्ववेद धार्मिक ग्रंथ है। नहीं, ये धर्म से पहले के ग्रंथ हैं। धर्म की अवधारणा बहुत बाद की है, ये उससे पहले से ग्रंथ हैं और हमने जो

[Prof. Manoj Kumar Jha]

आज तक पढ़ा है, उसमें कम से कम अथर्ववेद को धार्मिक ग्रंथ नहीं माना है। मैं इतना कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, यह आलोचना नहीं थी, कुछ सुझाव थे और मैं समझता हूं कि योग के लिए आपकी बेरुखी, जिसके लिए मैंने पहले कहा है, वह बेवफाई की श्रेणी में जा रही है, इसलिए उसे बंद कर दीजिए। उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। संसद के इस अपर हाउस के सभी सदस्यों ने इन दोनों ही बिलों का समर्थन किया है, इसलिए मैं भी इनके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मैडम, इन बिलों में, खास तौर से जो The National Commission for Indian Systems of Medicine Bill है, इस पर ज्यादा जोर दिया गया है, इसकी ज्यादा चर्चा हुई है, बनिस्बत के The National Commission for Homoeopathy Bill, जबकि पूरी दुनिया में होम्योपैथी दूसरी ऐसी विधा है, जो सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। ये दोनों महत्वपूर्ण बिल हैं, इसलिए मैं दोनों बिलों का समर्थन करता हूं। क्योंकि दोनों बिलों के माध्यम से जो भारतीय चिकित्सा शिक्षा पद्धति है, पैसा है, मेडिकल प्रोफेशन है और इन संस्थानों से जुड़े जो विभिन्न पहलू हैं, वे दोनों उनके विकास और नियमन के लिए उपयोगी होंगे।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि आज़ादी के 72 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन हम आज तक डब्ल्यूएचओ के मानदंड के अनुसार चिकित्सक नहीं बना पाए हैं, अभी तक डॉक्टर्स पैदा नहीं कर पाए हैं। भारत में डब्ल्यूएचओ के मानक के अनुसार 1,000 की जनसंख्या पर एक चिकित्सक की जरूरत होती है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि हमारा देश अभी भी इस बेंच मार्क तक पहुंचने से कोसों दूर है। अस्पतालों में लगने वाली लंबी लाइनें, मरीजों की बढ़ती संख्या इस बात को प्रमाणित करती है। एक तरफ तो डॉक्टरों की कमी है, वहीं दूसरी तरफ अगर इस बिल को देखें, तो जैसा मनोज झा जी और तमाम सदस्यों ने यह बात कही कि Yogic Science और Naturopathy को इस बिल में शामिल नहीं किया गया है। इस बिल में Yogic Science और Naturopathy को शामिल न करना इस बात को प्रमाणित करता है। पूरे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे नीति आयोग हो, चाहे संसद की स्थायी समिति हो, जिसके चेयरमैन प्रो. राम गोपाल यादव साहब थे और मैं भी उस समय उसका सदस्य था, और CCIM ने भी कोई मौकों पर योग और Naturopathy को कानूनी दायरे में लाने के स्पष्ट प्रावधान के लिए सिफारिश की है। देश में 45 मेडिकल कॉलेज 15 राज्यों में M.D. के courses और Under-graduation के courses चला रहे हैं। 6 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं, जो केन्द्र सरकार के अधीन चल रहे हैं, फिर भी योग और Naturopathy के लोगों को मेडिकल कॉलेज की स्थापना और उनके संचालन का या फिर उनसे जो pass out होंगे, 4.5 साल-5.5 साल की academic और एक साल

की internship करने के बाद जब वे बाहर निकलेंगे, तो उन डॉक्टर्स का क्या होगा? आखिर उनका भविष्य क्या है? जो Indian medicine systems हैं, इनको National Commission Bill में भी शामिल नहीं किया गया है। ऐसे लोग, जो डिग्रीधारक हैं, वे आखिर किस नाम से जाने जाएंगे? वे डॉक्टर्स हैं, वे झोला छाप के नाम से जाने जाएंगे। इससे यह प्रमाणित होता है कि इस बिल को पूरे तरीके से ठीक से नहीं पूरा किया गया है।

इस बिल में मेरी दृष्टि से जो सबसे बड़ी कमी लगी, वह Exit Exam की है। NMC में भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी और Standing Committee ने भी इसके बारे में अपनी बातें रखी थीं, जब इस पर चर्चा हुई थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, वे अपने उत्तर में जरूर बताएं कि final year में जो Exit Exam होगा, अगर बच्चा उसमें पास नहीं होता है, तो उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? क्या उसे दोबारा exam देने की permission मिलेगी या फिर से वह 10+2 के standard पर रह कर अपना जीवनयापन करेगा? एक बात यह है।

दूसरी बात यह है कि इन बिलों के आने के बाद तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने और उनको regulate करने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। क्या मंत्री जी जिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को permission देंगे, SC, ST और OBC के लोगों को reservation होगा कि नहीं? 2014 में जब से यह सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक यह पूरे देश में privatization को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा रही है। ये privatization तो करते जा रहे हैं, लेकिन privatization करने के बाद जो सरकारी नौकरियां थीं, जिनमें SC, ST और OBC के reservations होते थे, वे कटते जा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों में जो backlog है, चाहे आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज हों, चाहे यूनानी के मेडिकल कॉलेज हों, चाहे होम्योपैथी के मेडिकल कॉलेज हों, या फिर योग के हों, जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें जो ST, ST और OBC का backlog है, क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि वह backlog भरा जाएगा या कब तक भरा जाएगा?

मैं इन्हीं सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदया, National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019 Central Council of Indian Medicine को बदलने के लिए बना है। दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ आदि कुछ राज्यों के अंदर आयुष के डॉक्टर्स आज भी कुछ allopathy की practice करते हैं। Indian Medical Association ने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ case file किया, सुप्रीम कोर्ट में अभी stay है और इन क्षेत्रीय सरकारों के हिसाब से वे कुछ क्षेत्र तक practice कर भी सकते हैं और कर भी रहे हैं। कुछ हाई कोर्ट्स ने भी इस matter में stay कर रखा है। जब तक यह फैसला नहीं आता, वे आयुष के डॉक्टर्स यह practice करते रहेंगे। आपने इस बिल के

[श्री सुशील कुमार गुप्ता]

Clause 2(h) में परिभाषित किया है, "Indian System of Medicine" means the Ashtang Ayurveda, Unani, Siddha and Sowa-Rigpa Systems of Medicine whether supplemented or not by such modern advances as the Commission may, in consultation with the Central Government, declare by notification from time to time." इसमें यह क्लीयर नहीं है कि उन डॉक्टर्स का क्या होगा? मैं यह कहना चाहता हूं सरकार को अपनी पोज़िशन क्लीयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक से एक बढ़कर एक इलाज की पद्धतियां हैं। हर पद्धति को अपना सम्मान मिलना चाहिए और हर पद्धति के डॉक्टर्स को भी अपना सम्मान मिलना चाहिए। आज हमारे देश में कभी-कभी एलोपैथिक डॉक्टर्स आयुर्वेद के डॉक्टर्स को कहते हैं कि ये झोलाछाप डॉक्टर्स हैं। जब वह बच्चा पढ़कर, ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर, विभिन्न महानगरों और गांवों के अंदर जाकर सेवा करता है, और अपनी प्रैक्टिस करता है, तो उसके लिए इस प्रकार की बात कहना बिल्कुल उचित नहीं है। या तो सरकार ने उन्हें डिग्री ही नहीं दी हो, लेकिन जब उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स के ही समान डिग्री हासिल की है, तो फिर किसी को भी उन्हें झोलाछाप कहने का अधिकार न दिया जाए, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस बिल के अध्याय-4 के सब-क्लॉज़-I के अनुसार कमिशन का एक चेयरमैन होगा, 12 मेम्बर्स होंगे, 16 part time members होंगे और इन सभी मेम्बर्स को भारत सरकार appoint करेगी। इसके क्लॉज़ 11 (C) में एक Advisory Council होगी, जिसमें इस बोर्ड के सभी मेम्बर्स सदस्य होंगे, साथ ही हर राज्य एवं Union Territory का एक-एक नॉमिनी भी उसमें होगा। राज्यों के नॉमिनीज़ वहां की चुनी हुई सरकारें भेजेंगी, लेकिन Union Territories के नॉमिनीज़ को भारत सरकार appoint करेगी। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि दिल्ली समेत जिन Union Territories के अंदर चुनी हुई सरकारें हैं, वहां से एक-एक प्रतिनिधि Advisory Council के अंदर ले लीजिए, ताकि उन राज्यों को भी यह लगे कि हिन्दुस्तान का जो medicine system है, उसके अंदर सलाह देने में हमारा भी कुछ योगदान है। अगर आप उनसे उनके इस अधिकार को snatch करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन और कहना चाहता हूं कि सभी किस्म की डॉक्टरी के इग्ज़ाम्स के लिए पहले आप National Eligibility Test रखते हैं। बच्चे को इस कोर्स में दाखिला लेने से पहले National Eligibility Test देना पड़ता है, फिर पांच साल तक वह MBBS करेगा, फिर सात साल में Post Graduation की पढ़ाई पूरी करेगा, उसके बाद उसको National Exit Test देना पड़ेगा। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन उसके बाद आप कहते हैं कि अगर वह इलाज करने के बजाय किसी कॉलेज में एपॉइंटमेंट चाहता है, तो उसको एक National Teaching Eligibility Test

भी देना पड़ेगा। एक बार जब आपने किसी व्यक्ति को सम्पूर्ण डॉक्टर घोषित कर दिया और किसी का ऑपरेशन करने तक का अधिकार दे दिया, तो ऑपरेशन के लिए आप उसको मनुष्य का शरीर दे सकते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए उसको अलग से फिर एक टैस्ट देना पड़ेगा। जब उसने सात साल इस कोर्स के अंदर लगा दिए, दो-दो राष्ट्रीय टैस्ट भी दे दिए, फिर इस तीसरे टैस्ट की बाध्यता उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।

इसके साथ-साथ जैसा मेरे सभी साथियों ने कहा, मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि इसके अंदर आप योग और नेचुरोपैथी को भी ऐड करें, जिससे सारी दुनिया में एक अच्छा संदेश जाए। चूंकि इस क्षेत्र के अंदर हम सारी दुनिया की लीडरशिप कर रहे हैं, इसलिए योग और नेचुरोपैथी को भी इसके अंदर लाइए। जैसे अभी अन्य मैम्बर्स ने आपसे रिक्वेस्ट की, मैं भी कहना चाहता हूं कि जितने भी ये अलग-अलग बोर्ड्स बनने वाले हैं, उनके अंदर नॉमिनी के रूप में दो लोक सभा और एक राज्य सभा सदस्य भी जरूर रखे जाने चाहिए। आयुष की एक बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति हमारे हिन्दुस्तान में रही है, उन सबको सम्मान मिलना चाहिए। आयुष के विश्वविद्यालयों को स्थापित करने में राज्य सरकारों का भी कुछ सहयोग आना चाहिए, ताकि हम अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति से लोगों को अवगत करा सकें और पूरे हिन्दुस्तान के अंदर सस्ता इलाज उपलब्ध करवा सकें। हिन्दुस्तान के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति आयुष के माध्यम से इलाज करवाता है। एलोपैथिक डॉक्टर्स तो गांवों में जाने से भी घबराते हैं, जिससे गांव के स्तर तक एलोपैथी का इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता है। आयुष के डॉक्टर्स को विशेष रूप से हमें प्रमोट करना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। ऐसे कई असाध्य रोग हैं, जैसे विशेष तौर पर चर्मरोग हैं, जिसका इलाज एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में संभव ही नहीं है। ...**(समय की घंटी)**... मैं एक मिनट का समय और लूगा। यहां मैं अपने ही परिवार के एक सदस्य का उदाहरण बताना चाहता हूं। मेरा बेटा जब सात-आठ साल का था, तब मैं एक एलोपैथिक हॉस्पिटल का जनरल सेक्रेटरी था। उस समय उसके शरीर पर एक फुंसी हो गई थी। एक फुंसी का पानी फैलता था, तो दूसरी फुंसी हो जाती थी। मेरे सारे जानकार एलोपैथिक डॉक्टर्स ने कहा कि ऑपरेशन करके इसकी सारी स्किन से ये निकालनी पड़ेंगी, लेकिन उस समय मेरा जो फैमिली डॉक्टर था, उसने मुझसे कहा कि एक बार मुझे किसी अन्य डॉक्टर से भी सलाह लेने दीजिए। उन्होंने होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह ली और सिर्फ तीन दिन की दवाई के बाद मेरे बेटे के शरीर की सारी फुंसियां ठीक हो गईं। इसलिए मेरा मानना है कि हर किस्म की चिकित्सा पद्धति को बराबर सम्मान देते हुए, हिन्दुस्तान की इन चिकित्सा पद्धतियों को पूरी दुनिया के अंदर प्रचलित करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल के अंदर आप यह प्रावधान भी करें कि अगर एलोपैथिक डॉक्टर्स, आयुष के डॉक्टर्स को कम नज़र से आंकते हैं, तो सरकार उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का प्रबंध करे और किसी भी कीमत पर उनको झोलाछाप न कहा जाए, जय हिन्द।

LT. GEN (DR.) D.P. VATS (RETD.) (Haryana): Hon. Vice-Chairman, Sir, history of medicine is as old as the march of mankind, and, Prime Minister, Narendra Bhai Modi's vision of a Healthy India, a Fit India lies through the integrated system of Indian medicine and that vision leads to *Sarve Santu Niramaya.*

As far as structured courses and information is concerned, *vedas* are 5,000-years old and Ayurveda is an up-veda of four *vedas*. There has been a lot of discussion and controversy. I have been a senior health professional in Armed Forces, and, on behalf of the modern medicine or Allopathic medicine, I do not disown my fathers or forefathers, and, I claim it with pride that Allopathy is the daughter of Ayurveda. One of the best medical colleges in the country, rather second best, the Armed Forces Medical College, which I commanded ten years back, has its teaching complex named after Sushruta complex, the biggest auditorium is Dhanvantri Auditorium and the statue of Charak adorns the frontage of the college, though we give full respect to Pasteur, Alexander and Lister also. If we disown our parentage, then, we are not worth it. What an Allopathic Doctor looks through his eyes, as far as the present scenario is concerned. In Armed Forces, we say, threat perception and force assessment. I would like to draw the attention of the House, through you, that India's total population as on today is 135 crore. Around 97 lakh people die annually in India from all causes, and, it includes deaths in violence, road-accidents, cancer, life-style diseases and infectious diseases. Around 2.5 crore children are born annually, and, around 1.5 crore population is added to Indian population every year.

Now, as per the latest information given by the Ministry of Health and Family Welfare, there are more than 12 lakh Allopaths registered with the State Medical Councils and the Medical Council of India. Out of them, 10 per cent are NRIs or belong to Indian diaspora. Eighty per cent are available for work. There are approximately eight lakh Indian medicine doctors and it includes doctors from Homoeopath, Ayurveda, Unani, Siddha, Sowa Rigpa and all. Around two million nurses and 2.5 lakh dental doctors are there.

A word was spoken about the ethics. Dr. Hanumanthaiah spoke about it. My view is that we are not competitors and we do not look down upon. In the present scenario, we see that there is a threat of COVID-19 and it has been declared a pandemic. In today's newspaper, protocol for administering the allopathic medicine, that is, antiretroviral medicine has been given and it said that it will be given only in high-

risk cases, that is, to patients who are old, who are infirm, or patients with co-morbidities. Under these situations, allopathy badly needs all the traditional medicines, ayurveda and all alternative medicines, it starts from our kitchen. Whether it is ginger or whether it is *tulsi* or whether it is *giloy* or even Chyavanprash. I am thankful to my friend, Dr. Anurag of Baidyanath, in the Lok Sabha, who supplied a bottle to us two months back as a complement. Under these situations, if you are infected with coronavirus, 50 per cent will not develop symptoms and next 23 per cent will be having very mild symptoms. Now allopathy medicine is only to be administered in symptomatic cases. But what about its prevention? Ayurveda says use *amla, adarak, haldi*, etc. All these things are at least supportive food rich in Vitamin C. I will say these are complementary medicines to each other. They are not competitors to each other. We have to have a broader view. Certainly, I agree allopathy has galloped. And as far as other systems of medicine are concerned, their financial viability without emergency medicine may not be possible or feasible. Every speaker is saying that they are practising allopathy and without allopathy their financial survival, I won't say 'impossible' but certainly in this materialistic world it is not comfortable. Under these situations, the National Medical Commission took note of it and it has been given to the State Governments, because health is a State subject and State Governments are at liberty to give them bridge courses. In Maharashtra, I was commanding the Armed Forces Medical College where I stayed for 14 years in that complex and ayurvedic doctors are practising surgery, ophthalmic surgery and some of them are doing excellently well because trainability is to everybody and knowledge is not one individual's domain. It can be learnt anytime by anybody. Therefore, wheresoever there is a need we should give them a bridge course. In the National Medical Commission, because there was a reaction from allopaths, we took the middle path and the middle path is that we left it to the State Governments. If they feel so, they are welcome to do that. Even in your allopathic system, half of the practice of allopaths or I must say 80 per cent of the medical practice is supported by nurses. There are B.Sc. and M.Sc. nurses.

In all the systems of medicine, modernization is there. I want to draw the attention of the House to it. Even in the BAMS, in their initial basic sciences, they are taught Gray's anatomy, pharmacology and pathology. The basic sciences course is the same. The duration of the course is the same. Entry point is again after 10+2 with science and the length of course is also the same. Under these situations, they are being

[Lt. Gen (Dr.) D.P. Vats (Retd.)]

given emergency medicine course. Not only that, even in some corporate hospitals I have seen that house surgeon or residents are BAMS, and people are very happy with them. Having worked there for five-six months or one-two years, they also deliver. I will say that it is not a clash of civilizations, but it is a confluence of civilizations where one civilization is marching into another civilization. I won't call it piggybacking, but it is complementary.

On optimisation of specialists in Wellness Centres, ayurvedacharyas are posted at the levels of Community Health Centres and District Hospitals also. There is this issue of distribution of doctors, especially allopathic doctors, because the WHO requirement is one doctor per thousand people. That only Armed Forces can afford. Rest are not able to afford it because we post medical doctors by order and a doctor does a longer tenure at Siachen Glacier than even any infantry soldier. Other than those places, in a village of 10,000 population, even in my own village, doctor comes only twice a week. Medicine is not a part-time profession; it is a whole-time profession. I am proud that there are, at least, 42 doctors in Parliament and some of them really have a very objective view. *...(Time-bell rings)...*

Madam, I am a soldier and I will stick to timing. I don't know whether it is a warning bell or an ending bell, but I will say that let us optimize our resources seeing our threat perception. Let us come with each other; let us march with each other. In the end, I will specify the need of this Bill. Again, I will take it to the Armed Forces. One thing is unity of command and another is multiplicity of command. A need for the National Medical Commission was felt because the Medical Council of India was an autonomous body and it became a State within State. Here, in these Councils also, there is a mention of bottlenecks, delays, deliberate delays, etc. Under this, the responsibility of delivery of comprehensive healthcare is of the Health Minister of the State. Therefore, whosoever is responsible, there should be a unity of command and unity of command will come through these National Commissions Bills. As far as federation and democracy in the constitution of these Medical Commissions is concerned, these are subjects of science. There are fixed syllabi; there are fixed approaches. In the diagnosis of a disease, we don't do hand-raising and we don't take a majority decision. It is a scientific decision. I support the Bill. It is a comprehensive Bill. As far as Yoga and Naturopathy are concerned, yes, they are the

sciences with slow action. A separate Bill can be brought forward for that. Hon. Prime Minister, Modiji, has popularized it all over the world and we will not lag behind. Thank you very much.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Madam Vice-Chairman, I am not romantic on Indian systems of medicine like my senior colleague, Mr. Oscar Fernandes, or my friend, Dr. Sudhanshu Trivedi. But I am a believer in making the Indian system of medicine a much stronger system anchored in science, research and, most importantly, in written clinical documentation. I am well aware of the glorious traditions that the Indian medicine has had and I think the challenge before us is to make the Indian system of medicine an important element of our healthcare system based, as I said, on research. In 2015, a Chinese woman scientist got the Nobel Prize for her work on discovering a cure for malaria from Chinese systems of medicine and I see no reason why in the next ten years, an Indian scientist cannot get the Nobel Prize in Physiology and Medicine for discovering a cure for any of our ailments through the Indian systems of medicine. So, I come to this subject with an open mind. I do not come to this subject with a sense of awe or romance as far as the Indian system of medicine is concerned because I think we have to realize that science has moved on, research has moved on and experimentation has moved on, and the basis of modern medicine really is clinical documentation which has been the missing link in the Indian system of medicine.

Now, I want to have four very brief comments on the two Bills that we are passing. The National Health Policy of 2017 talks of integrative healthcare. The Kasturirangan Committee on the Draft Education Policy talks about medical pluralism. When I spoke on the AYUSH Ministry a couple of months ago, I myself advocated an integrated system of medical education. Not a separate system of medical education but an integrated system where you have core courses, where you have common foundation courses and then you have specialization either in modern allopathy or in the Indian system of medicine. Unfortunately, instead of integrating, we are now disintegrating. We passed the National Medical Commission Bill last year. Today, we are passing two Bills. One for Ayurveda and Unani and Siddha and another for Homeopathy and soon, presumably, the Minister would come with another Bill for a National Commission for Yoga and Naturopathy. Madam, instead of bringing them together, we are pulling them apart. What India needs is an integrated education system for medicine. We need

[Shri Jairam Ramesh]

medical colleges giving education for the first two-and-a-half years in common courses, in common foundation courses and, then, students opting to specialize either in Indian systems of medicine or Homeopathy or in modern Allopathy. So, I would request the Government to please create a system which would bring all these different institutions together. Maybe, now that you have different commissions, you need an apex super commission to bring all these commissions together so that education in medicine is imparted in an integrated manner. You can start in the All India Institute of Medical Sciences. You can start in JIPMER, in Puducherry, in the institutions that are under the control of the Central Government but I do wish to reiterate that India's healthcare requires integrated medical education where Allopathy, Homeopathy, Ayurveda, Unani, tribal systems of medicine, all get integrated for the first two-and-a-half to three years, and then specialization takes place. So, I request the hon. Minister to please give thought to bringing an integrated structure and not this silos that we have created.

Second comment that I have, Madam Vice-Chairman, is this. Unfortunately, all the great champions of federalism are not here. The Anna DMK is not here, the TRS is not here, the BJD is not here. ...*(Interruptions)*... No; DMK, you are with us. The BJD is not here. All the great champions of federalism are not here. Both these Bills are anti-federal. The National Medical Commission Bill was anti-federal and I want to place on record my deep sense of gratitude to the Home Minister. When it was pointed out to the Home Minister that the National Medical Commission Bill was going to undermine the rights of States, he intervened and convinced the Health Minister that the Bill should be amended. That is how in the National Medical Commission, out of 33 members, 9 members represent State Governments. Madam, in the National Commission for Indian System of Medicine, out of 29 members, only 6 represent the State Governments. Regarding Homeopathy, out of 20 members, only 5 represent the State Governments. Health is a State subject. Medical education is a Concurrent subject. You have to give equal responsibility to the States in this area. I am afraid, both the Bills, that we would soon be passing, actually weaken and undermine the States. I would request the hon. Minister to pay special attention to bringing a greater sense of participation for the State Governments.

My third point is on fees. ...*(Time-Bell rings)*...मैडम, दो मिनट में खत्म करूंगा। Again, in the National Medical Commission, the Home Minister saw the light of what

I was saying, when I had moved an Amendment and the Government accepted the Amendment, to regulate the fees for, at least, 50 per cent of the seats in private medical colleges and deemed universities. Both these Bills are silent on fees. There is no provision to regulate fees in private colleges. I would urge the hon. Minister to please give thought to the regulation of fees which is the biggest problem as far as medical education is concerned in our country.

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M. V. RAJEEV GOWDA) *in the Chair.*]

And the fact that there are no provisions in both these Bills on the regulation of fees is a serious lacuna in the Bills that we would be passing.

Finally, as I said in the beginning, Indian systems of medicine require modern systems of research. They require modern systems of science, and most importantly, they require modern systems of written clinical documentation. Under Clause 18 of the Indian System of Medicine Bill, hon. Minister, I would urge upon you to set up a board for research. Sir, you are setting up separate boards. I would urge you to set up a board for research. This would be a great signal that you will be sending to the Indian system of medicine community that you are valuing research as much as education. This Bill deals only with education. But, education without research is incomplete. Research without education is meaningless. Therefore, we need to integrate education and research and a very simple way would be to add under Clause 18 of this Bill, the Indian System of Medicine Bill, a separate board for research and bring topflight people in the modern scientific field to bring modern science into the practice, the theory of Indian systems of medicine. Finally, Sir, we have discussed Ayurveda; we have discussed Unani and we have discussed Siddha. My colleague and many others have talked of Yoga and Naturopathy. I also want to say that we have a very rich tribal system of medicine in our country. Now, one of the problems with the tribal system of medicine is its being oral. It has to be written. It has to be documented, as I said. Therefore, I would urge the hon. Minister in his over-arching jurisdiction over Indian systems of medicine also to give pride of place to tribal systems of medicine which have been practised in our country for ages, and which are still continuing to be practised today. Therefore, Sir, I welcome the fact that we are bringing these two Bills. There are shortfalls. There are lacunae. I would urge the hon. Minister to have these Bills passed, go back and see as to how the lacunae in these Bills can be addressed. The most important, in my view, is to bring modern science, modern

[Shri Jairam Ramesh]

research into Indian systems of medicine. Let us not *poo-poo* modern science. Let us not assume that we knew everything about modern science thousand years ago. Science has moved on. Science keeps moving. Research keeps moving and, ultimately, clinical documentation is what is important. Therefore, Sir, with these words, even though I do not belong to my good friend, Shri Oscar Fernandes's school of thought, and he keeps trying to convince me every time he sees me about the virtues of *gomutra* and all other traditional modes of treatment, my ears are open, my mind is open. I have a skeptical approach. I am agnostic. I am not atheist in this approach but as I said there are people who are romantics but also I should point out that there are also many hypocrites. Many people who sing the praises of Indian systems of medicine but at the first opportunity when their illness is concerned would like to go to a modern allopathic doctor. So, I am neither a romantic nor a hypocrite, I am a realist. I want the Indian systems of medicine to be a global player. I want it to be an integral player in the Indian healthcare system, and I think some of the points that I have made, if the hon. Minister can give it some attention, I would be most grateful. Thank you, Sir.

श्री गोपाल नारायण सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देने के साथ-साथ सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि 60-70 सालों के बाद वह इस विधा पर एक कमीशन बनाकर इसकी अपलिफ्टमेंट के लिए एक बिल सामने आई है।

आयुर्वेद में हमें दो तरह से विचार करना होगा। एक, रोग होने के बाद उसका इलाज और दूसरा, रोग न होते हुए बचपन से खाने, पीने, रहन-सहन की व्यवस्थाएं हैं, वे भी आयुर्वेद के सिस्टम में ही हैं। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस रोग को दूर रखने के लिए कौन-सा खाना खाना चाहिए और कौन-सा खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे, तो हमें समझने में सहूलियत होगी।

हमारे बहुत-से विद्वान सदस्यों ने बहुत सारे प्वाइंट्स दिए हैं। हमारे यहां पुराने सिस्टम में वैद्यिक सिस्टम की व्यवस्था अश्विनी कुमारों से शुरू होती है। उसके बाद, अथर्ववेद में भी इसके बारे में दिया गया। फिर धन्वन्तरि जी आए और उनके चेलों ने भी बहुत-सी विधाएं दीं। अगर आज हम उसको renovate कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ मॉडर्न शब्द खत्म हो जाएगा। मॉडर्न व्यवस्था allopathic में चल रही है। यदि हम research करना शुरू करेंगे तो पुरानी उसी व्यवस्था में, जो हमारे पूर्वज लोग, ऋषि-महर्षि लोग दे चुके हैं, पुन: उनको हम re-ensure करेंगे और फिर हम पेड़-पौधे और जड़ी-बूटियों पर आ जाएंगे, हम chemicals

पर नहीं आएंगे। इन दोनों का संबंध modernisation से नहीं बनता। इसलिए मैं मंत्री महोदय को दो-तीन सुझाव दूंगा। आज आयुर्वेद का upliftment करने की आवश्यकता है। समाज में विश्वास दिलाने की ज़रूरत है, ताकि इस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट हो और इस विधा को लोग समझें, लोग इस पर depend करें। हमने पिछले 60-70 सालों में इसमें कोई व्यवस्था नहीं की। हमारी जितनी भी modernised technology से chemicals पर आधारित medicines आयी हैं, उन पर हमें ज्यादा विश्वास होने लगा है। आज अगर हमको रिसर्च करनी है तो हमारे गांवों में जो दादी के नुस्खे कहे जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों पर उसका निदान दिया हुआ है, हमें उस पर रिसर्च करनी होगी और उसको आयुर्वेद की संस्था में लाना पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आपने जो कमेटी बनाने की लिस्ट दी है, उसमें सभी bureaucrats और पढ़े-लिखे लोग हैं। बड़े-बड़े देशों में वैद्य लोग हैं, जो आज भी उसकी practice करते हैं और उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, उनका विश्वास भी है और उनके पास रोज़ हज़ारों लोग दवा लेने के लिए जाते हैं। क्या उस कमेटी में आप उन लोगों को शामिल नहीं कर सकते हैं, अगर वे कमेटी में शामिल होंगे तो वे आयुर्वेद के बारे में ज्यादा अच्छे सुझाव देंगे, क्योंकि वे practitioner हैं।

आज हमारे यहां एक प्राचीन system चला आ रहा है कि रोग से हो या हमारे संस्कार से हो, हम हर एक पुरानी चीज़ को अपनी परम्परा में ढाल लेते थे। आज भी हमारे गांव में एक परम्परा बनी हुई है कि अगर आपको पेट में गैस की बीमारी होती है तो आपको क्या-क्या खाना-पीना है और कैसे आपको रहना है? अगर हम इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को लें और आगे बढ़ते जाएं तो हमको बहुत बड़े रिसर्च आवश्यकता नहीं है। हमारे गांवों में already समूची विधाएं हैं। जैसे अभी जयराम रमेश जी ने कहा है कि आदिवासी क्षेत्र में जो लोग हैं, वे अभी भी modern technology नहीं जानते हैं। इसलिए इस पर रिसर्च करनी है कि हम आयुर्वेद को develop करने के लिए जो छोटी-छोटी विधाएं पूरे देश में अलग-अलग चल रही हैं, उनको समेट कर एक सिस्टम में लाएं और सिस्टम में लाकर लोगों में विश्वास जागृत करें।

तीसरा यह कि हमारे यहां बड़े-बड़े medical colleges चल रहे हैं, AIIMS बन रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं आयुर्वेद से जुड़े हुए वैद्यों की भी बहाली होनी चाहिए, ताकि दोनों का parallel effect सामने आ सके कि अगर allopathic medicine होती है तो साथ-साथ एक आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, कुछ विधाएं ऐसी होती हैं जो पेट से संबंधित, गैस से संबंधित होती हैं, जिनका आयुर्वेद में ज्यादा अच्छा इलाज है। हम medical colleges खोलते समय अगर आठ मेडिसिन डॉक्टर्स को बहाल करते हैं तो उसमें हम एक वैद्य को compulsory क्यों नहीं करते हैं या जो आयुर्वेद विद्यालय हैं, उनमें एक certain limit की education को फिक्स करके उनमें से लोगों को यहां लाएं। अगर उन्हें लाएंगे तो एक साथ parallel डॉक्टर्स जो OPD में बैठते हैं, वहां उनका competition होगा तो पब्लिक में ज्यादा जागृति आएगी। उससे

म.प. 4.00 बजे

[श्री गोपाल नारायण सिंह]

लोगों में विश्वास पैदा होगा। अगर हम इस technique को develop करते हैं तो लोगों पर economic प्रभाव कम पड़ेगा, क्योंकि आज medicine इतनी costly होती जा रही है, क्योंकि हमें उसके basic structure में basic chemicals को दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। एक पेपर में हमने पढ़ा था कि चीन में virus फैलने के बाद हमारे यहां केमिकल्स महंगे होंगे। वहां से केमिकल्स नहीं आएंगे, इसलिए दवा महंगी हो जाएगी। आज हम इस परिस्थिति में हैं, लेकिन आयुर्वेद की जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी दवाएं बनती हैं, वे सब हमारे देश में, जड़ी-बूटियों में हैं। हमारे देश में जितनी जड़ी-बूटियां हैं, आज चीन border areas से उन्हें ले जा रहा है। हमारे देश में herbal के नाम पर जो चीज़ें पैदा होती थीं, आज अमेरिका और इंग्लैण्ड उन पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे यहां sugar के बारे में... जैसा हमारे फर्नांडिस साहब ने गठिया के बारे में कहा, पैर के दर्द के बारे में कहा, इनके लिए छोटी-छोटी चीज़ें सब जगह खुली हुई हैं। हमारे हैल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि इन सब विधाओं पर रिसर्च करके उन पर एक नया सिस्टम बनाए, ताकि लोगों को आगे चलकर समझने, पढ़ने और सोचने में अच्छा हो और इसका विस्तृत प्रचार हो।

आयुर्वेद पर प्रचार नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि गरीब तबके के लोग होम्योपैथी की दवाई लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जो लोग जानकार नहीं हैं और साधारण लोग, कभी आयुर्वेद की दवाई लेने नहीं जाते हैं। हमें इसे promote करने की आवश्यकता है। अगर हम इसको डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें आयुर्वेदिक विधा को डेवलप करना पड़ेगा और उसका प्रचार-प्रसार करना पड़ेगा। सर, इतने आयुर्वेदिक कॉलेजेज़ खुले हुए हैं। मैं चार-पांच कॉलेजेज़ में गया और दो-चार डॉक्टर्स को अपने यहां लाना चाहता था। कहीं भी इस स्तर की पढ़ाई नहीं होती है। यदि उनसे बेसिक चीज़ पूछते हैं, तो वे जानकारी भी नहीं दे पाते हैं, इसलिए जितने आयुर्वेदिक कॉलेज़ेज हैं, उनके status को increase करना, उनके लिए पढ़ाई के अवसर भी बढ़ाना, तब उनको प्रैक्टिस में लाना और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के साथ उनको parallel खड़ा करना होगा। सरकार को उन डॉक्टर्स के parallel व्यवस्था देनी होगी, ताकि वह देखे कि गरीब लोगों का वहां से सस्ती दवाई लेने के बाद बढ़िया इलाज होता है। ...(**समय की घंटी**)... और महंगा इलाज जो हम केमिकल दवाई लेकर करते हैं, वह थोड़ा हमको महंगा पड़ता है, इसलिए उन लोगों का diversion उधर हो, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें इसके विकास के लिए आवश्यक हैं। अगर हम इस पर ध्यान देकर आगे चलेंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा।

महोदय, दूसरी चीज़ यह है कि अभी योग पर बात आई, नेचुरोपैथी पर बात आई। यह एक स्वस्थ रहने की एक परंपरा है, निदान नहीं है। बचपन से योग की ट्रेनिंग दी

जाती है और यदि आदमी जीने के साथ-साथ योग करते रहेगा, तो उसकी लाइफ लंबी होगी। इस पर अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी भी योग की तरह एक सिस्टम है, इसलिए सबको मिलाकर एक सिस्टम जो आप ले रहे हैं, उसके लिए अलग-अलग आयोग बनाते चलेंगे, तो जैसा कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह इतना विस्तृत हो जाएगा कि सब आपस में एक-दूसरे के साथ mix up हो जाएंगे या clash होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आयुर्वेद का सिस्टम अलग है — आयुर्वेद है, उसमें नेचुरोपैथी भी है, योग भी है और दवा की व्यवस्था भी है और उसमें रिसर्च भी है। रिसर्च करने में हमें बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जितने वेद और उपनिषद् हैं...(**समय की घंटी**)... सब में इसकी विधा दी गई है, लेकिन हम उनको न पढ़कर, अपने गांव के व्यवहार में, देहातों में जो परंपराएं हैं, वे भी आयुर्वेदिक सिस्टम पर बनी हुई हैं, उन विधाओं को लेकर अगर हम उस पर ज्ञान लेकर उसे लिपिबद्ध कर लें और उसको हम implement करना शुरू कर दें, तो इसका विकास ज्यादा होगा और लोगों को समझ में आएगा और यह विधा ज्यादा popular होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): सर, मेरे ध्यान में एक बात आई है कि Standing Committee ने जो suggestions दिए थे, उनके ऊपर ध्यान न देने का क्या कारण है? यह पहली बात है। हम लोगों को उसके बारे में मालूम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि नीति आयोग ने भी यह बात कही थी और उन्होंने ड्राफ्ट भी दिया था, उसको भी आपने साइड में रखा हुआ है। तीसरी बात ऐसी है कि कैबिनेट ने भी कुछ suggestions दिए थे और प्रेस नोट भी आया था। उन्होंने कुछ amendments का सुझाव दिया हुआ है। आप उन्हें करने वाले हैं कि नहीं, यह मुझे मालूम नहीं है। अगर यह सारा मामला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह आप Select Committee को दोनों बिल देंगे, तो और अच्छा होगा और इसके ऊपर विचार होना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है।

महोदय, यह बिल लोक सभा में introduce किया गया था। उसके बाद Standing Committee में भेजा गया था। कैबिनेट ने कुछ amendments के सुझाव दिए थे, उसका क्या हुआ? उसके बारे में मालूम नहीं है। एक तो Medical Pluralism की बात करते हैं, लेकिन पूरी तरह से बिल में integrated practice के बारे में संदेह निर्माण हो रहा है। सर, मैं महाराष्ट्र से आता हूं। वहां होम्योपैथी के 80,000 डॉक्टर्स हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। उनको इसमें इन्टिग्रेटेड डालना चाहिए, वह नहीं डाला गया है। आप यहां पर यह नहीं करेंगे, तो महाराष्ट्र में इसका क्या होगा? होम्योपैथी के बारे में जो बिल है, वह जो क्लॉज़ 52 है, उसमें amendment करके, उसमें इन्टिग्रेटेड प्रैक्टिसिज़ के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो नीति आयोग ने आपको इस संबंध में कहा था। नेशनल कमीशन

[श्री हुसैन दलवई]

फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में जो ड्राफ्ट किया गया था, उस वक्त यह कहा गया था। यह फरवरी, 2017 का ड्राफ्ट था। उन्होंने यह कहा था कि Yoga and Naturopathy regulation with separate Board for Yoga and Naturopathy, उन्होंने सेपरेट बोर्ड की बात की है। वह इसमें कहीं भी नहीं आता है। वह इसमें क्यों नहीं आता है? एक तरफ हमारे प्रधान मंत्री की बात बार-बार की गई है कि प्रधान मंत्री ने योग के लिए बड़े पैमाने पर बात कही है और योग पूरी दुनिया में गया है। इसे मैं नहीं मानता हूं क्योंकि दुनिया में योग पहले ही गया था। उसका advertisement प्रधान मंत्री जी ने बहुत तरीके से किया है। यह बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई doubt नहीं है कि योग से बहुत फायदा होता है।...(**समय की घंटी**)... सर, क्या मेरा समय पूरा हो गया है? मैंने तो अभी बोलना शुरू किया है। यह मुझे नहीं मालूम है कि आप इसे क्यों टाल रहे हैं?

दूसरा, आयुष, योग, नेचुरोपैथी के बारे में कई लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, उन पर आपने कोई दखल नहीं दिया है, मुझे लगता है कि यह ठीक बात नहीं है। Central regulation by the statutory cover means, जो quack डॉक्टर्स होते हैं, अगर आप इसमें statutory cover नहीं लाएंगे, तो इससे quack डॉक्टर बनेंगे। कई ऐसा बोलते हैं कि जिनको बच्चे नहीं होते हैं, उनको बच्चे कैसे होंगे, यह मैं देखता हूं। इस तरह के advertisement होते हैं। जब हम उत्तर भारत में घूमते हैं, तो हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ होता है कि बवासीर होगी, तो ऐसा करो, वैसा करो और हमें मिलो। ऐसी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल से उसका रेग्युलेशन होना बहुत जरूरी है। Yoga and Naturopathy have been an integral component of Indian system of medicine since 1970 in the Indian Government and in several States. The Central Council for Research in Yoga and Naturopathy which was earlier under the Ministry of Health and Family Welfare and now, it is under the Ministry of AYUSH, has been in existence since the year 1979. यह अभी की बात है, ऐसा मत समझिए। यह जो ज़ाहिर किया जाता है, ऐसा लगता है कि यह देश 2014 से चालू हुआ है। 2014 में हमने अंग्रेजों को यहां से निकाला और उन्होंने इनके हाथ में सौंप दिया, जो अंग्रेजों के बारे में हमेशा अच्छा बोलते थे, इसलिए उन्होंने इनके हाथ में सौंप दिया और यह सब कर रहे हैं। आप इसे जरा बंद कीजिए, यह पहले से हो रहा था।

मैं कुछ सजेशन दूंगा।...(**समय की घंटी**)... आप नेचुरोपैथी, योग और सिद्ध का एक बोर्ड बनाइए। मुझे लगता है कि आप इनके बारे में बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे सेलेक्ट कमेटी में जाने दो और उसकी चर्चा होने दो। हम बिल्कुल इसके समर्थन में हैं। इसका विरोध करने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक बात जो बार-बार

इन्होंने कही, वह सबसे महत्व की बात है। इन सारी बातों पर रिसर्च होने की बहुत जरूरत है, वरना ऐसा ही होता रहेगा कि यह ऐसा मूत्र, वैसा मूत्र है, इसको इस्तेमाल करो। इससे लोग गलत फायदा भी उठाते रहते हैं। ऐसा मत करो, अगर उसमें से कुछ अच्छा है, तो जरूर ले लो। मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन बिना रिसर्च ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ऐसा मुझे लगता है। बिना रिसर्च आजकल जो प्रचार चालू है, मुझे whatsapp पर आता है, लोग गाय के पीछे दौड़ते रहते हैं। मुझे लगता है कि यह गलत बात है। आप प्रचार करिए कि ऐसा मत करो। कोरोना के बारे में भी यह बोला जाता है कि ऐसा करेंगे, तो कोरोना नहीं होगा, वैसा करेंगे, तो कोरोना नहीं होगा, यह बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ बातें ऐसी हैं, जो हमारे समाज में पहले से ही चल रही हैं। एक तो मैं आयुर्वेद के बारे में कहूंगा कि इसमें बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें एलोपैथी में नहीं मिलती हैं, यह मेरा तजुर्बा है। होम्योपैथी के बारे में भी आप क्लॉज़ 52 में integration की बात रखिए। मैंने आपको अमेंडमेंट दिया है, आप उसको करिए। उसके बाद बिल को पास करिए, नहीं तो इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजिए, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है, धन्यवाद।

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): सर, यह जो इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल ऐक्ट, 1970 है, इसका मेंडेट यह था कि इसमें शिक्षा का स्तर पूरे भारत वर्ष में एक हो और जो भी वैद्य या प्रेक्टिशनर डॉक्टर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका स्तर भी एक होना चाहिए, लेकिन इस ऐक्ट के जरिए से ये दोनों बातें हो नहीं पाई हैं। यही बात होम्योपैथी के बारे में भी है। होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल ऐक्ट, 1973 आया था, उससे भी अपेक्षा थी कि ये दोनों बातें पूरी होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पहले भी इस तरह की कोशिश 2005 और 2010 में हुई थी, लेकिन उस वक्त पोलिटिकल विल इतनी मजबूत नहीं थी, उनकी इसको करने की इच्छा थी, परन्तु ऐसा हुआ नहीं। उस वक्त आयुर्वेद की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया था। मैं माननीय मंत्री श्री श्रीपाद यसो नाईक को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस काम को किया है।

दूसरी बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को सुधारने के लिए जो यह बिल आया है, यह इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार एक proactively काम करने वाली सरकार है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं स्टैंडिंग कमेटी में भी था, जहां पर प्रो. राम गोपाल यादव जी की अध्यक्षता में पूरा काम हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद में बड़ा potential है और आयुर्वेद का होना जरूरी है। इसके बारे में, मैं अपना एक अनुभव बताना चाहूंगा। मैं एक ट्रायबल एरिया में camp के लिए गया था। वहां पर एक 30-35 लोगों की टोली थी और वह बहुत दूर-दराज का एरिया था। मैंने उन लोगों से पूछा कि तबियत ठीक रहने के लिए आप लोग क्या करते हो? वे लोग बोले कि हमारे यहां एक वैद्य है, वह वैद्य हमारी तबियत

[डा. विकास महात्मे]

ठीक रहे, इसके बारे में बताते रहते हैं। मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूं, इसलिए मैंने जानना चाहा कि वह वैद्य कमाता कैसे है, उसको पैसे कैसे मिलते हैं? उसको आप लोग क्या देते हैं? इस पर वे बोले कि हम सभी मिलकर उसको अनाज देते हैं, पूरे साल में जो भी अनाज लगता है, वह हम लोग देते हैं। मैंने कहा कि यह बात तो सही है कि आप उसको साल भर का अनाज देंगे, लेकिन जब कोई बीमार पड़ता है, तब आप उसको एडिशन में और क्या देते हैं? उन्होंने बताया कि जब किसी को बीमारी होती है, तो उस घर से उसको अनाज नहीं मिलेगा, यानी ट्रीटमेंट इसलिए है कि सभी हेल्दी स्वस्थ रहें। यहां पर आयुर्वेद का जो मकसद है, वह एलोपैथी से बहुत अलग है। यह एक लाइफस्टाइल है जिससे कि हम बीमार न हों, इसके ऊपर फोकस किया जाता है और इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आयुर्वेद को समझना है और उसे आगे बढ़ाना है। इस बिल के जरिए से हम आयुर्वेद को आगे बढ़ा पाएंगे, ताकि हम सभी हेल्दी रहें। जैसे अभी वेलनेस सेंटर्स बनाए हैं, वे इसलिए बनाए हैं, ताकि हम सब हमेशा आरोग्यमय रहें। आयुर्वेद आगे बढ़ना चाहिए, यह बहुत जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि कई बार हमें लगता है कि modern medicine या एलोपैथी में कैमिकल फैक्टरी से बनकर दवाइयां आती हैं, वैसा नहीं है। आप यदि कहेंगे कि chloroquine जिसको मलेरिया के लिए हम हमेशा यूज़ कर रहे हैं, उस chloroquine को सबसे पहले ट्रायबल ने देखा। ट्रायबल लोगों को जब भी बीमारी होती है या बहुत बुखार आता है, तो वे एक पेड़ की टहनी या स्टेम को यूज़ करते हैं। बाद में इस पर रिसर्च हुई और रिसर्च के बाद में पता चला कि उसमें quinine है और quinine की टैबलेट बनने लग गई और उससे मलेरिया ठीक होने लग गया। महोदय, फिर Quinine से Chloroquine निकला, क्योंकि Quinine के बहुत disadvantages थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि basic drug पेड़-पौधों से निकलती है और बाद में उस पर research की जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले उससे Quinine निकली। Research के बाद Chloroquine बना। वैसे ही आज जिसे हम वियाग्रा कहते हैं, वह भी पौधे से ही बनाया गया है। पहले वह पौधे से पाया गया और फिर बाद में आजकल फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि आयुर्वेद में बहुत potential है, लेकिन potential है, इसका मतलब यह नहीं है कि लोग उसे अपनाएंगे। यह तब तक नहीं होगा जब तक कि हम लोगों को उसके बारे में सबूत देकर नहीं बताएंगे और इसके लिए ही रिसर्च की बहुत आवश्यकता है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने प्रिएम्बल में ही लिखा है कि रिसर्च के लिए यह बिल बहुत उपयोगी होगा और आगे चलकर यह बहुत फायदेमंद साबित होगा। मुझे अभी उसमें रिसर्च के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। मेरे मन में सवाल उठता है कि क्या मेरा अनुभव ही evidence या सबूत है? उदाहरण के तौर

पर मैं बताना चाहूंगा कि कुछ साल पहले माहीम में एक दरगाह है और उसके पीछे एक creek है। वहां समुद्र का पानी आता है। वहां ऐसा हुआ कि मीठा पानी निकलने लगा। जब लोगों को पता लगा कि वहां मीठा पानी निकल रहा है, तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि समुद्र में खारे पानी के बजाय मीठा पानी निकल रहा है। वे इसे चमत्कार मानने लगे। लोगों ने उसे पिया, तो उनकी बीमारियां दूर होने लगीं। चूंकि वह स्थान दरगाह के पीछे था, तो वहां बहुत लोग गए और उन्होंने वह पानी पिया, तो ठीक हो गए। इसलिए वहां बहुत लोग जाने लग गए। यह एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बल्कि हजारों लोगों ने यही कहा और यह सिलसिला सात दिनों तक चला। मैं यह real बात कह रहा हूं। बाद में उस पानी के बारे में रिपोर्ट आई कि आसपास की केमिकल फैक्ट्रियों से कुछ केमिकल्स के लीकेजेज़ हो रहे थे, इसलिए पानी में मीठापन आ रहा था। सबका अनुभव यह है कि उस पानी को पीने से बीमारियां दूर हुईं, यह उनका अनुभव है, लेकिन chemicals की वजह से पानी मीठा हुआ यह सबूत या evidence है, जो बाद में आया, Research के कारण आया।

महोदय, मैं शेफर्ड कम्युनिटी से हूं। हमारे यहां लोग भेड़ और बकरियां पालते हैं और उन्हें लेकर हम घूमते हैं। आमवस के दिन एक जगह पर हमारे लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं और वे भेड़ के कान में कुछ बोलते हैं। जैसा वे कान में बोलते हैं, वैसा ही होता है और बीमारी दूर होती है, ऐसा उनका मानना है क्योंकि यह उनका अनुभव है। जब मैंने उनसे यह कहा कि यह आपकी अंध-श्रद्धा है, तो वे बोले कि यह हम सब का अनुभव है। आप मुझसे नहीं, बल्कि 100 लोगों से पूछ लीजिए, उनकी बीमारी ठीक हुई है। मैं बोला कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन वे बोले की आप यदि पार्लियामेंट में बोलते हैं, तो आपका वह अनुभव सही है, लेकिन मैं कॉमन मैन हूं, मैं सर्वसाधारण हूं, इसलिए मेरा अनुभव गलत है, आप यह कैसे कह सकते हैं और यह आपका कैसा सिद्धान्त है? इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हम केवल अनुभव से यह नहीं बोल सकते कि यह सही है, या यही सत्य है। बल्कि उसके लिए supporting evidence चाहिए। Evidence, यानी क्या? मैं यह कहता हूं कि यह दवा मैंने ली और मेरा बुखार कम हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उस दवा को आप सबको बांट सकते हैं और यह भी नहीं कह सकते कि यह बुखार के लिए अच्छी दवा है जब तक इसका कोई सबूत न हो। इसलिए आजकल जो हो रहा है, उसे समझना बहुत जरूरी है और उसी प्रकार से जैसे श्री जयराम रमेश जी ने कहा कि इसके लिए आपको मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, वैसे ही डबल ब्लाइंड रिसर्च स्टडी है।

महोदय, जैसा अभी डा. अमर पटनायक जी ने बताया था कि randomized control trial है। मैं बताना चाहता हूं कि डबल ब्लाइंड में क्या होता है। यदि मैं कहूं कि इस दवा से बुखार कम होता है, तो उसकी टेबलेट बनाई जाएगी और बुखार वाले 1,000 लोगों को यह टेबलेट दी जाएगी और वैसी ही 1,000 टेबलेट्स उसी रंग की, लेकिन उसमें अंदर

[डा. विकास महात्मे]

दवा नहीं होगी, वह फिर अन्य 1,000 लोगों को दी जाएगी। जो ट्रीटमेंट दे रहा है तथा जो टेम्परेचर नाप रहा है, उन दोनों को पता नहीं होता है कि कौन सी गोली में क्या है। फिर बाद में तय होता है कि सचमुच में उस दवा से किसे कितना फायदा हुआ। मान लीजिए कि एक गोली से 1,000 लोगों में से 100 लोगों का बुखार कम हुआ और दूसरी गोली से भी 100 लोगों का बुखार कम हुआ, तो समझ में आता है कि इस दवा से कोई असर नहीं हुआ, जिन लोगों का बुखार कम हुआ, वह अपने आप कम हुआ, उसमें दवा का कोई रोल नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से स्टडी जब तक नहीं होगी, तब तक हम नहीं कह पाएंगे कि फलानी दवा से 10,000 लोगों को आराम हुआ, इसलिए वह दवा सही है। नहीं तो हमारे shepherds का जो अनुभव है, वैसा ही हमारा अनुभव रहेगा। मुझे पता है कि यूनानी और आयुर्वेद पद्धति में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को यदि यूज़ में लाना है, तो हमें साइंस का evidence based, not experience based निर्णय बताना पड़ेगा और जब तक हम उस तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक यह सही नहीं होगा। Experience (अनुभव) और Evidence (सबूत) — इन दोनों में जो अंतर है उसे समझना होगा और research के माध्यम से उन्हें जोड़ना होगा। योग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि योग बहुत important है और लोगों ने इसको इसलिए भी accept किया है कि उसमें पूरी तरह से रिसर्च हुई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जी ने स्वयं लीडरशिप लेकर, योग दिन की शुरुआत विश्वभर में की। इसीलिए यह योग सब तरफ पहुंच रहा है और सभी को उसका फायदा हो रहा है। जैसे yoga part of ayurveda है, वैसे ही आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और बाकी और जो भी हैं, होम्योपैथी है, यदि हम इनका साइंटिफिक बेसिस पर एविडेंस बेस्ड प्रमोशन करेंगे, तो ये लोगों में, पूरे देश में, पूरे विश्व में अच्छी तरीके से पहुंच सकती हैं। अगर ऐसा होगा, तो उसका क्रेडिट भी हमें मिल सकता है और हमारी वजह से "सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:" हो जाएगा। मेरा यह कहना है कि ऐसा करने से सभी लोग निरामय हो जाएंगे। इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे ये बिल लेकर आए हैं। इसमें स्टेट के लिए कहा गया था...**(समय की घंटी)**,,, लेकिन उसमें एक एडवाइज़री कमेटी है, जिसमें सभी स्टेट्स का representation है, इसलिए मुझे लगता है कि जैसे इसमें स्टेट्स का representation और डॉक्टर्स का भी representation है, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर शब्द डालकर फिज़िशियन.. महोदय, आपने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, in the Statement of Objects and Reasons of this Bill, — the earlier Indian Medicine Central Council (IMCC) Act, 1970 has not served the purpose — it is said, “to streamline

the functioning of Central Council of Indian Medicine and to bring transparency mechanism for grant of permission of medical institutions and improve the standards of medical education." Now, the present enactment will serve the purpose or not, I don't know, but I support the Bill. I wanted to submit to the Minister a few suggestions with regard to this enactment. Previously, it was referred to the Department-related Standing Committee which examined it. It recommended 32 suggestions, out of which only 15 were accepted. The important aspect is, Yoga and Naturopathy have been given discriminatory treatment in this Bill. The Minister has to take care of it. Another thing is, one Member from Lok Sabha and one Member from Rajya Sabha are to be considered while constituting the National Commission. That recommendation is also important. That has to be considered. In fact, the Medical Council is a professional body. Proportional representation has not been given in the National Commission. Only six members have been given. Being a professional body, it requires more number of representation in the National Commission. Likewise, medical treatment is a State subject. The States must be given proper representation. It has been given in the Bill. Now it is required to constitute a Commission by giving appropriate representation to the States. As far as the appellate body is concerned, it is a quasi judicial body, but it requires independent powers, but the Bill does not provide such independent power as far as appellate body is concerned.

The Indian system of medicine has to be re-oriented at the present stage. ...*(Time-bellrings)*... The post-graduate diploma in clinical cardiology course has been conducted by the Indira Gandhi National Open University between 2006-2013. There are 1,700 graduates, but no recognition was given. They have approached the Delhi High Court. The Delhi High Court categorically directed the Central Government to consider it afresh on the ground that before commencing the course, the IGNOU had not obtained prior permission under Section 10A. Accordingly, the decision is not sustained and quashed. Recognition has to be given. Despite the directions of the hon. High Court of Delhi, it was not considered by the Ministry. I request the hon. Minister to consider it, to give recognition to PGDCC. There are 1700 cardiologist graduates. It has to be considered. Ultimately, my senior colleague, Shri Jairam Ramesh, has suggested that it requires an integrated medical education system. I support the same. Unless that system is introduced, the purpose and the objects of the Bill may not be fulfilled. Thank you, Sir.

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग, 2019 और होम्योपैथिक आयोग, 2019, ये दो महत्वपूर्ण विधेयक आज सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं। मैं समझता हूं कि इन दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद देश की शिक्षा पद्धति में बहुत आमूलचूल सुधार होगा, क्योंकि इनमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

मान्यवर, पूरे देश की आयुर्वेदिक शिक्षा को एक सूत्र में पिरोने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा होगी और इसके साथ ही साथ faculty members का selection भी राष्ट्रीय स्तर पर होगा तथा राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होगा। इस आयोग के अंतर्गत चार बोर्डों का गठन होगा, जो स्वायत्त रूप से अपना-अपना काम करेंगे। मैं समझता हूं कि इन विधेयकों के पारित होने के बाद निश्चित रूप से इनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और इनसे हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना है।

मान्यवर, मुझे एक पीड़ा है। हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने विस्तार से इस पर चर्चा की और महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, लेकिन आयुर्वेद के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे आयुर्वेद परिणामपरक हो, आयुर्वेद का इलाज परिणामपरक हो, उसके लिए यह आवश्यक है कि हमारी जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं, वे उस उन्नत कोटि की हों, जिसके नतीजे लोगों को दिखाई पड़ें, लोगों को अनुभव हों, जिससे उनकी प्रमाणिकता बढ़े। वैदिक काल से लेकर जो आयुर्वेदिक दवाएं थीं, उनको बनाने के अलग तरीके होते थे और वे दवाएं विधि-विधान के साथ बनती थीं, लेकिन आज वे आयुर्वेदिक दवाएं बड़े पैमाने पर फैक्टरियों में बनती हैं, इसलिए उनके वे परिणाम नहीं आते। मान्यवर, आयुर्वेद में रस, रसायन, कल्प, भस्म, इस तरह की चीजें तमाम प्रयास के बाद, शिद्दत के बाद, वैद्य लोग कई दिनों तक प्रयास के बाद भस्म इत्यादि तैयार करते थे और जिस मर्ज़ के लिए जो दवा होती थी, उसके प्रभावकारी परिणाम आते थे, लेकिन आज इस वैज्ञानिक युग में सारी चीजें बड़ी-बड़ी फैक्टरियों में बन रही हैं, packaging हो रही है, बहुत अच्छे टैबलेट्स बन कर आ रहे हैं, लेकिन वे परिणाम नहीं आते हैं। मैं समझता हूं कि जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, उसमें आयुर्वेद को इस देश में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है कि हम अपनी आयुर्वेदिक फार्मेसीज़ को सुदृढ़ करें, आयुर्वेदिक फार्मेसीज़ की quality को improve करें, वहां पर बनने वाली दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए कठोर मानक बनाए जाएं और वे ही दवाएं मार्केट में आएं और लोगों तक, मरीजों तक पहुंचें। इसके लिए हमारी जो पौराणिक व्यवस्था थी, चाहे सुश्रुत संहिता हो, चाहे चरक संहिता हो, उनमें देवाओं के बनाने का जो तरीका है, उस तरीके से दवाएं बननी चाहिए। हमारा पूरा आयुर्वेदिक विज्ञान प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हम प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से दवाएं तैयार करते हैं। आज भी यह मान्यता है कि अर्जुन का जो पेड़ होता है, उसकी छाल से जो टैबलेट बनती है, वह हृदय रोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है। नीम के पेड़ की पत्तियां निश्चित रूप से एंटीबॉयोटिक के रूप में काम करती हैं। ऐसी बहुत सी दवाएं हैं, जो हम प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से तैयार करते हैं।

लेकिन उन जड़ी-बूटियों की खोज, उन पर शोध, अध्ययन और उसके अनुरूप उन दवाओं को तैयार करना, रसायन तैयार करना, यह एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जहां आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को या भारतीय चिकित्सा पद्धति को आपने इस विधेयक के माध्यम से एक मजबूत आधार दिया है, उससे राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से योग्य चिकित्सक निकल कर आएंगे, जो अच्छे चिकित्सक होंगे, राष्ट्रीय मानक के अनुरूप होंगे तथा शोध और अनुसंधान का काम भी होगा। अज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारी देवाओं के बनाने में जो शोध और अनुसंधान का कार्य करने के लिए हमारी जो फार्मेसीज़ हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। आज जो सबसे बड़ी चिंता है कि आयुर्वेदिक दवाओं का परिणाम उतना अच्छा नहीं मिलता, उसका कारण है कि आयुर्वेदिक दवाओं के बनाने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें शिथिलता बरती जाती है। औद्योगिक ढंग से नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अंदर आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने की जो प्रक्रिया हमारे ऋषियों, मनीषियों ने निर्धारित की थी, हमारे पुराने वैद्यों ने जिस ढंग से उनको बनाया था, तभी वे दवाएं लाभकारी हुआ करती थीं। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में भारतीय चिकित्सा पद्धति की ख्याति पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि अच्छे चिकित्सक हों, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक अच्छी दवाएं नहीं होंगी, तब तक उन दवाओं से लोगों को, मरीजों को लाभ नहीं होगा। जब तक मरीजों को लाभ नहीं होगा, तब तक उस दवा की या उस चिकित्सा पद्धति की स्वीकार्यता नहीं होगी। हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा और मैं उनको बधाई दूंगा कि वे जो दोनों विधेयक लाए हैं, ये भारतीय चिकित्सा पद्धति में निश्चित रूप से मील के पत्थर साबित होंगे और इनसे देश की चाहे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हो, चाहे यूनानी हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति हो, इनमें बहुत सुधार होगा। लेकिन हमें इसके साथ ही आयुर्वेदिक दवाओं, यूनानी दवाओं और होम्योपैथिक दवाओं की गुणवत्ता के ऊपर भी विशेष ध्यान देना होगा। जब तक हम गुणवत्तापरक दवाएं नहीं बनाएंगे, तब तक हमको उनके व्यापक परिणाम नहीं मिलेंगे और जब तक व्यापक परिणाम नहीं मिलेंगे, तब तक हमारी चिकित्सा पद्धतियों की स्वीकार्यता नहीं होगी। भारतीय चिकित्सा पद्धति अपने में पूर्ण है और उसमें जटिल से जटिल रोगों का इलाज है। जिस बीमारी में एलोपैथिक चिकित्सक ना कर देते हैं, उन रोगों का इलाज आयुर्वेदिक चिकित्सा के अंतर्गत होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये दोनों बहुत ही शानदार विधेयक आप लेकर आए हैं, लेकिन हमें आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए भी उतनी ही प्राथमिकता के साथ प्रयास करना होगा, ताकि हम उत्कृष्ट कोटि की आयुर्वेदिक दवाएं बना सकें, जो लाभकारी हों, परिणामकारी हों। इससे हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति की स्वीकार्यता बढ़ेगी। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक): सबसे पहले मैं सभी माननीय सदस्यों का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने 'राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2019' और 'राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019' को समर्थन दिया और आप सभी माननीय सदस्यों का हमें सपोर्ट मिला। मुझे लगता है कि इससे आगे आने वाले समय में भी इसी तरह काम करने के हमारे हौसले और भी बढ़ जाएंगे। जो-जो भी माननीय सदस्य यहां बोले, उन सभी ने कई suggestions दिए और ज्यादा से ज्यादा सदस्यों ने इस बिल को समर्थन दिया है।

महोदय, आयुष मंत्रालय की दो Councils थीं, 'Central Council of Indian Systems of Medicine' and 'Central Council of Homoeopathy. 1970 में एक अधिनियम बना था और 1973 में Homeopathy Council बनी थी। इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों का समग्र विकास और इनकी शिक्षा संबंधी जो काम थे, उनको ये दोनों ही Councils देख रही थीं। उक्त अधिनियम में 'भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्' संबंधी जो समयानुसार परिवर्तन किए जाने चाहिए थे, वे नहीं हुए, जिसके कारण इसके तंत्र में ऐसे अवरोध पैदा हो गए, जिससे चिकित्सा शिक्षा पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अनेक व्यवधान पैदा हुए।

महोदय, इसके 50 साल के बाद जब माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी ने कार्यभार संभाला, तब Ministry of Health and Family Welfare में आयुष एक छोटा सा विभाग मात्र था, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसका एक अलग मंत्रालय बना दिया और उसके बाद निश्चित तौर से इसके काम में गति आई है।

'भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्' की कार्यप्रणाली को सुचारु बनाने, चिकित्सा संस्थाओं को अनुमति देने, तंत्र में पारदर्शिता लाने और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में चिकित्सा शिक्षा के मानकों में सुधार के लिए केन्द्र सरकार 'भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2005' को राज्य सभा में लाई थी, लेकिन किसी न किसी कारण से वह आगे बढ़ नहीं पाया। 2019 में हम 'राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग' का बिल लाए थे, लेकिन तब हमने उसे विद्ड्रॉ कर लिया था। केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2016 में 'भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम' की समीक्षा के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। उक्त समिति ने 'भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2018' को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लोक सभा में पेश करने और 'राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2018' की ही तर्ज पर अधिनियमित करने की सिफारिश भी की। उनकी सिफारिश के बाद ही 7 जनवरी, 2019 को 'भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2019' राज्य सभा में पेश किया गया था। उसके बाद ये दोनों विधेयक स्टैंडिंग कमेटी में पेश किए गए और स्टैंडिंग कमेटी के जो suggestions थे, उनमें से मैक्सिमम को हमने इस विधेयक में accommodate किया

है, उसके बाद ही यह बिल आपके सामने लाया गया है। ज्यादातर सभी माननीय सदस्यों ने इसके बारे में पूछा है। भारतीय चिकित्सा पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा व्यवसाय और चिकित्सा संस्थाओं से संबंधित सभी पहलुओं के विकास और विनियमन के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग का गठन और आयोग को सलाह देने व सिफारिशें करने के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन उसमें किया हुआ है। निम्नलिखित नामों से चार स्वायत्त बोर्डों का गठन, अर्थात् स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर आयुर्वेद शिक्षा को विनियमित करने और उसके मानकों का निर्धारण करने के लिए आयुर्वेद बोर्ड बनाया हुआ है।

स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा शिक्षा को विनियमित करने और उसके मानकों को निर्धारित करने के लिए यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड बनाने की सिफारिश है। चिकित्सा संस्थाओं का निरीक्षण करने और उनका निर्धारण व मूल्यांकन करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति हेतु चिकित्सा निर्धारण एवं मूल्यांकन बोर्ड तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों एवं व्यावसायिकों के बीच व्यावसायिक आचरण को नियमित करने तथा चिकित्सा आचार-विचारों को बढ़ावा देने और भारतीय चिकित्सा पद्धति के सभी लाइसेंसशुदा चिकित्सकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आचार और पंजीकरण बोर्ड भी बनाया है।

स्नातकपूर्व चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा का आयोजन इसमें हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासी के रूप में करने के लिए लाइसेंस देने हेतु एक राष्ट्रीय एग्जिट टैस्ट का भी आयोजन किया है।

महोदय, इसके आगे भारतीय चिकित्सा पद्धति के शिक्षक के रूप में ही नियुक्ति देने के लिए भी राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन है। नई चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने की पद्धति है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर को बनाए रखने का तरीका भी है।

भारत में और भारत के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा अर्हता को मान्यता देना और मान्यता को वापस लेना या अर्हता को अमान्य करना है।

महोदय, मुझे यहां कहने में आनन्द का अनुभव होता है कि आज आयुर्वेद भारत में ही नहीं, बल्कि कई राष्ट्रों से हमारे पास डिमाण्ड आ रही है कि हमारे पास आप इस संदर्भ में रिसर्च और कोऑपरेशन में हमें एमओयू करिये, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कम-से-कम 14 अन्य राष्ट्रों में हमारे आयुर्वेद, होम्योपैथी और योग के एमओयू बन गये हैं और कम-से-कम 10 युनिवर्सिटीज़ में हमें चेयर प्रदन किए हैं और हमारे प्रोफेसर्स वहां जाकर पढ़ा रहे हैं और कम-से-कम 28 राज्यों में 58 इंफॉर्मेशन सेन्टर्स भी बनाये गये हैं।

[श्री श्रीपाद यसो नाईक]

महोदय, मुझे यह बताने में बहुत खुशी हो रही है कि यह जो एनसीआईएम विधेयक, 2019 को राज्य सभा में माननीय सभापति जी द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित स्थायी समिति के समक्ष परीक्षण और रिपोर्ट के लिए भेजा गया था। राज्य सभा सचिवालय ने 27 नवम्बर, 2019 के अपने पत्र के द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की स्थायी समिति की भांति चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2019 की 115वीं रिपोर्ट की प्रति को मंत्रालय द्वारा आगे विचार करने के लिए अग्रेषित किया था। स्थायी समिति ने विधेयक पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और संशोधनों और आशोधनों की सिफारिश की। मंत्रालय ने स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संशोधन किए जाने की आवश्यकता पर उनके स्वयं के विचारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चिकित्सा पद्धति हेतु राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2019 में कुछ संशोधनों/अतिरिक्त खंडों का प्रस्ताव किया।

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की जांच की गई और तद्नुसार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के साथ आमेलित किया गया। मैं उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैक्सिमम जो स्टैन्डिंग कमेटी से सुझाव आए थे, कम-से-कम दो-तीन को छोड़कर जो उसमें बाकी थे, मेरे ख्याल से वे हमने पूरे ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): आपने इसमें 50 परसेन्ट से कम माने हैं।

श्री श्रीपाद यसो नाईक: जो प्रावधान इसमें हैं, हमें ऐसा लगा कि उनके करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आगे आने वाले रूल में एकोमोडेट कर लेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Please address the Chair.

प्रो. राम गोपाल यादव: आप इतना आश्वासन दे दीजिए कि योग, नेचुरोपैथी पर जल्दी बिल लाएंगे या इसमें समाहित करके बोर्ड बनायेंगे। सर, योग और नैचुरोपैथी वाली जो बात है, जैसा मैंने कहा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अंडर जो समिति गयी थी, उन्होंने रिकमंड किया था कि योग और नैचुरोपैथी के लिए अलग बिल बनायें। हमने बिल की तैयारी भी की है और वह consideration में है, यह मैं निश्चित तौर से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। वह हमारे विचाराधीन है और जल्दी से जल्दी हम इसके ऊपर विचार करेंगे।

सर, मैं एक बार फिर सभी मेम्बर्स का, जिन्होंने यहां हमें सपोर्ट दिया है, उस सपोर्ट का शब्दों में तो मैं आभार नहीं जता सकता हूं, क्योंकि आयुर्वेद — AYUSH system of medicines करीब पांच साल से पहले शुरू हुआ है। 50 सालों में इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, यह वैसी के वैसी ही थी। जो बजट 100 करोड़ का था, वहां 50 करोड़ भी

खर्च नहीं होता था। मैं खुशी से कहना चाहता हूं कि इन पांच सालों में हमने जो बजट खर्च किया है, पूरे के पूरे 100 परसेंट खर्च किया है। हमारे एक माननीय सांसद ने इसकी मांग भी की है, आप सभी जानते हैं। आप लोगों ने हमारे लिए इतने प्रयास किये कि बजट और बढ़ा कर दे दो, लेकिन हम मानते हैं कि हो जाएगा। हमें जो कुछ साधन-सामग्री मिली, इससे यह जो आयुष का कार्यभार है, उसको हम पांच सालों में आगे बढ़ाने में थोड़ा-बहुत कामयाब हुए हैं। हमें थोड़ा और मौका चाहिए। आप सभी माननीय सदस्यों ने जो सजेशंस दिये हैं, वे सजेशंस सही रूप से आने चाहिए और इसके बारे में हम विचार करेंगे और जो कुछ हम रूल्स में ले सकते हैं, उनको रूल्स के अंडर हम डाल देंगे और उसकी कार्रवाई करने में आगे बढ़ेंगे।

माननीय राम गोपाल यादव जी, जो कुछ मैंने कहा है, present Ministry has set up a Yoga Certification Board, जो आपने कहा था, वह हमने already एक Yoga Certification Board set up किया है। बिल जब आयेगा, तब यह जो बोर्ड है, तब तक इससे व्यवस्था देख लेंगे।

कई मेम्बर्स ने अपनी बात कही है। डा. अमर पटनायक जी ने कहा था कि, "In order to promote research, all Director-Generals of AYUSH Research Council are Members of this Commission as per the recommendation of the Parliamentary Standing Committee." इन सब को हमने इसमें सम्मिलित किया हुआ है। सभी Research Councils के जो DGs हैं, इन सबको हमने सम्मिलित किया हुआ है। माननीय श्री बांडा प्रकाश जी ने कहा था कि, "Central Government is Second Appellate Authority. The First Appellate Authority is the Commission. Creating a separate Appellate Tribunal will delay the decision-making process." इसीलिए जो कुछ है, पहले जो कमिशन होगा, इसके बाद में मंत्रालय है और जरूरत पड़ी तो फिर इसके ऊपर भी निश्चित तौर से हम विचार करेंगे।

श्री के. सोमप्रसाद जी ने इसके बारे में जो बोला है कि "The provision allows the Chairman and Members of the Commission to accept the employment in any private medical institution within two years from demitting the office of the Commission. The Central Government shall take due procedure and ensure that there is no conflict of interest."

महोदय, हमारे कई मेम्बर्स ने हमें अच्छे सुझाव दिये हैं। डा. विनय सहस्रबुद्धे, जो यहां हमारे मेम्बर हैं, उन्होंने आयुर्वेद का महत्व जिस तरह से हमें बताया है, मुझे लगता है कि हमें विनय सहस्रबुद्धे जैसे लोगों की guidance चाहिए। माननीय प्रो. राम गोपाल यादव जी का जो मार्गदर्शन हमें हर रोज़ मिलता है, इनके सजेशंस के आधार पर इस आयुष मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने में हम निश्चित तैर से कामयाब होंगे।

[प्रो. राम गोपाल यादव]

माननीय मानस रंजन भूनिया जी ने कहा था कि सबसे पहले जो हम चाहते हैं कि वह चाहे कोई सी भी पैथी हो, सभी पैथीज़ में अपनी-अपनी एक अलग ताकत है। कई सदस्यों ने कहा है कि medicines का integration होना चाहिए। यह काम आयुष ने already शुरू किया हुआ है। कई जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है या दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां integration का काम already शुरू हुआ है। आखिर हम सभी का प्रयास किसके लिए है, जो पेशेंट है, वह जल्दी ठीक होना चाहिए। इसीलिए यह प्रयोग सभी जगहों पर अभी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में चालू हुआ है। हमारे यहां 'आयुष' नाम की एक scheme है। उसमें हमारे Primary Health Centers में भी सभी तरह के डॉक्टर्स बैठते हैं। जिसको जो पैथी चाहिए, जो मेडिसिन चाहिए, वह लेकर आता है। अभी integration का प्रमाना शुरू हुआ है और यह integration निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा।

महोदय, प्रो. राम गोपाल यादव साहब ने कहा कि कमेटी की तरफ से 33 recommendations थे, उनमें से आधे को भी नहीं माना गया, मैंने इस संबंध में बताया है कि जिनको हम रूल्स में adjust कर पाएंगे, उनको करेंगे। जो रूल्स हैं, उनमें इनमें से कई अपने आप adjust हो जाते हैं। हमने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगा, तो हम इनके ऊपर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

महोदय, हमें यह बिल इसलिए लाना पड़ा, क्योंकि हमें आयुष पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए और ताकत चाहिए। कुछ जगहों पर ऐसे कॉलेजेज़ थे, जो नाम के लिए कॉलेजेज़ थे, जहां यह कहा जाता था कि आप एडमिशन ले लीजिए, आप कॉलेज आइए या मत आइए, आप सर्टिफिकेट लेने के लिए आ जाइएगा। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे आयुष पद्धति के जो डॉक्टर्स हैं, उनमें confidence नहीं है, practice करने का confidence नहीं है। उनकी यह बात सही है, क्योंकि जब तक डॉक्टर कॉलेज में जाकर पढ़ेगा नहीं, तब तक उसमें प्रैक्टिस करने का confidence कहां से आएगा? इसमें इस तरह के जो strict rules हैं, आज उनकी बहुत जरूरत थी। एक-दो रूम में जो कॉलेज चलते थे, हमने ऐसे सभी कॉलेजेज़ को बंद करवा दिया। सिर्फ कागज पर ऐसे जो कॉलेजेज़ थे, उनको हमने बंद करवा दिया। हमें ये सब करने के लिए और ताकत चाहिए, इसलिए हम ये दोनों बिल्स आपके सामने लेकर आए हैं। आगे ऐसे ही कुछ और कानून आएंगे और हम उन पर अमल कर पाएंगे।

महोदय, यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने योग और नैचुरोपैथी के बारे में बोला है, हमने उसके बारे में assure किया है कि जैसा नीति आयोग ने कहा है, उसी के मुताबिक हम नया बिल लाने के बारे में विचार करेंगे और जल्दी ही इस तरह का बिल लेकर आएंगे। माननीय सदस्यों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, हम उन सुझावों पर निश्चित तौर पर विचार

करेंगे। इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, इनसे हमें निश्चित तौर पर ताकत मिलेगी। हम आयुष मिशन के तहत NAM के जरिए कार्यक्रम चलाते हैं और सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में अपना योगदान दे रहे हैं। हमने NAM के तहत जो एक 50 बेड्स हॉस्पिटल की स्कीम बनाई है, उस स्कीम के तहत अब 100 से ज्यादा हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल बनाने की योजना है। हम इसी तरह से बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली के नजदीक बदरपुर में हमने ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद शुरू किया है। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप एक बार वहां जाकर देखिए। हमने 2017 में उसको शुरू किया था। आज के दिन वहां दो हजार से भी ज्यादा पेशेंट्स ओपीडी में आ रहे हैं। यह 100 बेड्स का हॉस्पिटल है और हर दिन फुल रहता है और पेशेंट को जगह नहीं मिलती है। इस प्रकार से लोगों का रुझान आयुर्वेद के प्रति, आयुष के प्रति बढ़ रहा है। चूंकि हमारे institutions की संख्या बढ़ रही है, हमारा काम बढ़ रहा है, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ताकत भी चाहिए और उसी ताकत के लिए हम इस बिल के माध्यम से आपके सामने आए हुए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि हमें आगे भी आपका सहयोग चाहिए और विनती करता हूं कि ये जो बिल्स हैं, इनको पारित करके हमें और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए सहूलियत दें। मैं ज्यादा न बोलते हुए, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): I shall first put the motion regarding consideration of the National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019 to vote. The question is:

> "That the Bill to provide for a medical education system that improves access to quality and affordable medical education, ensures availability of adequate and high quality medical professionals of Indian System of Medicine in all parts of the country; that promotes equitable and universal healthcare that encourages community health perspective and makes services of such medical professionals accessible to all the citizens; that promotes national health goals; that encourages such medical professionals to adopt latest medical research in their work and to contribute to research; that has an objective periodic and transparent assessment of medical institutions and facilitates maintenance of a medical register of Indian System of Medicine for India and enforces high ethical standards in all aspects of medical services; that is flexible to adapt to the changing needs and has an effective grievance redressal mechanism and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

In Clause 2, there is one Amendment (No. 4) by the hon. Minister.

CLAUSE 2 – DEFINITIONS

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 4) That at page 2, lines 22-23 *for* the words, “whether supplemented or not by such modern advances as”, the words, “supplemented by such modern advances, scientific and technological development as” be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): In Clause 4, there are nine Amendments; Amendments (Nos. 49 and 50) by Dr. T. Subbarami Reddy; Amendment (No. 56) by Shri K. Somaprasad and Amendments (Nos.5 to 10) by the hon. Minister. Dr. T. Subbarami Reddy; not present. Shri K. Somaprasad, are you moving?

CLAUSE 4 – COMPOSITION OF COMMISSION

SHRI K. SOMAPRASAD: Sir, I move:

(No. 56) That at page 4, line 7, *for* the word “six”, the word “ten” be *substituted*.

SHRI JAIRAM RAMESH: What are the Amendments by the hon. Minister? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): They would have been provided to you as part of the Bill.

SHRI JAIRAM RAMESH: No; nothing is provided. ...*(Interruptions)*... What are the Amendments?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): I request the Minister to ensure that the Members have a copy of the Amendments that you are moving. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: May I raise one issue? ...*(Interruptions)*... Did we discuss the amended Bill or the un-amended Bill? What Bill did we discuss?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): The Amendments are being voted on now. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: But where are the Amendments? ...*(Interruptions)*... We have not got the Amendments. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): They have been circulated. That is the information I have. ...*(Interruptions)*... I have been informed that the Amendments were circulated on the 28th of February, 2020. They have been circulated. You would have received it much earlier. Since many weeks have passed, you may not have paid attention.

I shall now put the Amendment (No. 56) by Shri K. Somaprasad to vote. ...*(Interruptions)*...

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Now, Amendments (No.5 to 10) by the hon. Minister.

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 5) That at page 3, line 18 *for* the word, "twelve", the word "fifteen" be *substituted*.

(No. 6) That at page 3, line 19 *for* the word, "sixteen", the words "twenty-three" be *substituted*.

(No. 7) That at page 3, *after* lines 37, the following be *inserted*, namely:–

"(fa) the Director General, Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi;

(fb) the Director General, Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi;

(fc) the Director General, Central Council for Research in Siddha, Chennai;".

[Shri Shripad Yesso Naik]

(No. 8) That at page 4, line 5, *after* the word, "Sanskrit", the words "Urdu, Tamil," be *inserted*.

(No. 9) That at page 4, line 7 *for* the word, "six", the word "ten" be *substituted*.

(No. 10) That at page 4, *for* lines 10 to 14, the following be *substituted*, namely:

"(c) six members from Ayurveda, one member each from Siddha, Unani and Sowa-Rigpa, to be appointed from amongst the nominees of the States and Union territories, under clause (ca) of sub-section (2) of Section 11, in the Advisory Council for Indian System of Medicine, for a term of two years in such manner as may be prescribed.".

The question was put and the motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): In Clause 5, there are two Amendments; Amendment (No. 51) by Dr. T. Subbarami Reddy and Amendment (No. 11) by the hon. Minister. Dr. T. Subbarami Reddy is not present. Now, the Minister.

CLAUSE 5 – SEARCH COMMITTEE FOR APPOINTMENT OF CHAIRPERSON AND MEMBERS

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 11) That at page 4, line 32, *after* the word, "Sanskrit", the words "Urdu, Tamil," be *inserted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): In Clause 6, there is one Amendment (No.57) by Shri K. Somaprasad.

CLAUSE 6 – TERM OF OFFICE AND CONDITIONS OF SERVICE OF CHAIRPERSON AND MEMBERS

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Sir, I move:

(No. 57) That at page 5, lines 38 to 41, be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 7 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): In Clause 8, there are two Amendments; Amendment (No. 52) by Dr. T. Subbarami Reddy and Amendment (No. 12) by Shri Shripad Yesso Naik. Dr. T. Subbarami Reddy is not present. Now, the Minister.

CLAUSE 8 – APPOINTMENT OF SECRETARY, EXPERTS, PROFESSIONALS, OFFICERS AND OTHER EMPLOYEES OF COMMISSION

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 12) That at page 6, line 26, *for* the words, "quality assurance", the word "accreditation" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 8, as amended, as added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): In Clause 9, there is one Amendment (No. 13) by Shri Shripad Yesso Naik.

CLAUSE 9 – MEETINGS OF COMMISSION

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 13) That at page 7, *for* lines 1 to 3, the following be *substituted*, namely:–

"(6) A person who is aggrieved by any decision of the Commission, except the decision rendered under sub-section (4) of Section 30, may prefer an appeal to the Central Government against such decision within fifteen days of the communication of such decision.".

The question was put and the motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): In Clause 10, there are two Amendments; Amendment (No. 53) by Dr. T. Subbarami Reddy and Amendment (No. 14) by Shri Shripad Yesso Naik. Dr. T. Subbarami Reddy is not present. Now, the Minister.

CLAUSE 10 – POWERS AND FUNCTIONS OF COMMISSION

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 14) That at page 7, *after* line 21, the following be *inserted*, namely:–

"(ha) frame guidelines for determination of fees and all other charges in respect of fifty per cent of seats in private medical institutions and deemed to be Universities which are governed under the provisions of this Act;".

The question was put and the motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): In Clause 11, there are two Amendments; Amendments (Nos. 15 and 16) by Shri Shripad Yesso Naik.

CLAUSE 11 – CONSTITUTION AND COMPOSITION OF ADVISORY COUNCIL FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 15) That at page 7, *for* lines 38 and 39, the following be *substituted*, namely:–

"in that State, possessing qualifications in the Indian System of Medicine, to be nominated by that State Government, and one member to represent each Union territory, who is the Vice-Chancellor of a University in that Union territory, possessing qualifications in the Indian System of Medicine,"

(No. 16) That at page 7, *for* lines 41 to 44, the following be *substituted*, namely:–

"Provided that where the Vice-Chancellor possessing qualifications in the Indian System of Medicine is not available, a Dean or a Head of Faculty possessing qualifications in the Indian System of Medicine shall be nominated;

(ca) one member to represent each State and each Union territory from amongst elected members of the State Medical Council of Indian System of Medicine, to be nominated by that State Medical Council;

(cb) the Chairman, University Grants Commission;

(cc) the Director, National Assessment and Accreditation Council;".

The question was put and the motion was adopted.

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, just one moment. Is it a Bill, or, is it an amended Bill? It should be made clear by the Minister. He should clear this to the entire House. My belief is that the Parliamentary Affairs Minister should scrutinize the entire thing before submitting all these Amendments inside the House by the Minister. He should make it clear to the Chairman of this House as to how many Amendments the Minister wants to bring before the House.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

MR. CHAIRMAN: Bhattacharya*ji*, you have made your point. In Clause 12, there are two Amendments; Amendments (Nos. 17 and 18) by the Minister.

CLAUSE 12 – FUNCTIONS OF ADVISORY COUNCIL FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 17) That at page 8, line 3, *for* the words, "training and research", the words "training, research and development" be *substituted*.

(No. 18) That at page 8, line 6, *for* the words "training and research", the words "training, research and development" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 13, there is one Amendment (No. 54) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is not present.

Clause 13 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 14, there is one Amendment (No. 19) by the Minister.

5.00 P.M.

CLAUSE 14 – NATIONAL ELIGIBILITY-CUM-ENTRANCE TEST

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 19) That at page 8, *after* line 35, the following be *inserted*, namely:–

"(4) The Commission shall specify by regulations the manner of admission of students to undergraduate courses who are exempted under sub-section (1).".

The question was put and the motion was adopted.

Clause 14, as amended, was added to the Bill.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, there is no Clause 14 here. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I will go through it. Please sit down. ...*(Interruptions)*... You can't move away from your seat. You have brought a point to my notice. I will examine it.

You have made your point. I am capable of understanding what you are saying. I will attend to that. ...*(Interruptions)*... In Clause 15, there is one Amendment (No. 20) by the Minister.

CLAUSE 15 – NATIONAL EXIT TEST

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 20) That at page 8, *after* line 45, the following be *inserted*, namely:–

"(4) Any person with a foreign medical qualification shall have to qualify National Exit Test for the purpose of obtaining licence to practice as medical practitioner of Indian System of Medicine and for enrolment in the State Register or the National Register, as the case may be, in such manner as may be specified by regulations."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

Clauses 16 to 18 were added to the Bill.

...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You need not tell him and he need not tell you. If there is anything, that will be told to me. ...*(Interruptions)*... Please. Don't make any gesticulation. He is a Member. He has got the right to say. If there is some substance in what he is saying, I will attend to that. Otherwise, I will be moving on. Please. This is the House. We must respect each other.

In Clause 19, there are two Amendments; Amendment (No. 55) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is not present. Also, there is one Amendment (No. 21) by the Minister. ...*(Interruptions)*...

CLAUSE 19 – COMPOSITION OF AUTONOMOUS BOARDS

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 21) That at page 9, *for* lines 45 and 46, the following be *substituted*, namely:–

"and the remaining two Members shall be accreditation experts;"

The question was put and the motion was adopted.
Clause 19, as amended, was added to the Bill.
Clauses 20 to 23 were added to the Bill.

...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: In Clause 24, there is one Amendment (No. 22) by the Minister.

CLAUSE 24 – MEETINGS, ETC., OF AUTONOMOUS BOARDS

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 22) That at page 10, line 41, *for* the words, "sixty days", the words "thirty days" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.
Clause 24, as amended, was added to the Bill.
Clauses 25 and 26 were added to the Bill.

...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. You also hear what the hon. Members are saying. ...*(Interruptions)*... In Clause 27, there is one Amendment (No. 23) by the Minister.

CLAUSE 27 – POWERS AND FUNCTIONS OF BOARD OF ETHICS AND REGISTRATION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 23) That at page 11, *after* line 47, the following be *inserted*, namely:–

"(d) exercise appellate jurisdiction with respect to the actions taken by a State Medical Council under section 30."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 27, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 28, there are two Amendments; Amendment (No. 58) by Shri K. Somaprasad and Amendment (No. 24) by the Minister. Shri K. Somaprasad, are you moving your Amendment?

CLAUSE 28 – POWERS AND FUNCTIONS OF MEDICAL ASSESSMENT AND RATING BOARD FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): I move:

(No. 58) That at page 12, lines 14 to 25, be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendment (No. 24) by the Minister.

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 24) That at page 12, line 10, *after* the words, "new medical institution", the words "or to start any postgraduate course or to increase number of seats," be *inserted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 28, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 29, there are nine Amendments; Amendments (Nos. 25 to 33) by the Minister.

CLAUSE 29 – PERMISSION FOR ESTABLISHMENT OF NEW MEDICAL INSTITUTION

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 25) That at page 12, line 38, *after* the words, "new medical institution", the words "or start any postgraduate course or increase number of seats" be *inserted*.

(No. 26) That at page 13, lines 2 and 3, *for* the words, "six months", the words "three months" be *substituted*.

(No. 27) That at page 13, *after* lines 4 and 5, the following be *substituted*, namely:–

"Provided that before disapproving such scheme, an opportunity to rectify the defects, if any, shall be given to the person concerned."

(No. 28) That at page 13, line 9, *for* the words, "six months", the words "three months" be *substituted*.

(No. 29) That at page 13, line 11, *for* the words, "six months", the words "three months" be *substituted*.

(No. 30) That at page 13, line 13, *for* the word, "forty-five", the word "fifteen" be *substituted*.

(No. 31) That at page 13, line 14, *for* the word, "thirty", the word "seven" be *substituted*.

(No. 32) That at page 13, lines 15 and 16, *for* the word, "forty-five", the word "fifteen" be *substituted*.

(No. 33) That at page 13, line 19, *after* the words, "any other expert", the words "having integrity and experience in medical profession" be *inserted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 29, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There is one Amendment (No. 34) for Insertion of New Clause 29A by Shri Shripad Yesso Naik.

INSERTION OF NEW CLAUSE 29A – CRITERIA FOR APPROVING OR DISAPPROVING SCHEME

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 34) That at page 13, *after* line 20, the following be *inserted*, namely:–

"29A. While approving or disapproving a scheme under section 29, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, or the Commission, as the case may be, shall take into consideration the following criteria, namely:–

(a) adequacy of infrastructure and financial resources;

(b) whether adequate academic faculty, non-teaching staff, and other necessary facilities have been provided to ensure proper functioning of medical institution or would be provided within the time-limit specified in the scheme;

(c) whether adequate hospital facilities have been provided or would be provided within the time-limit specified in the scheme;

(d) such other factors as may be prescribed:

Provided that, subject to the previous approval of the Central Government, the criteria may be relaxed for the medical institutions which are set up in such areas as may be specified by the regulations".

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: In Clause 30, there are two Amendments; Amendments (Nos. 35 and 36) by Shri Shripad Yesso Naik.

CLAUSE 30 – STATE MEDICAL COUNCIL

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 35) That at page 13, *for* lines 46 to 49, the following be *substituted*, namely:–

"(4) A medical practitioner of Indian System of Medicine who is aggrieved by the decision of the Board of Ethics and Registration for Indian System of Medicine, may prefer an appeal to the Commission within sixty days of communication of such decision."

(No. 36) That at page 14, lines 1 and 2 be *deleted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 30, as amended, was added to the Bill.

Clause 31 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 32, there is one Amendment (No. 37) by the Minister.

CLAUSE 32 – RIGHTS OF PERSONS TO BE ENROLLED IN NATIONAL REGISTER AND THEIR OBLIGATIONS THERETO

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 37) That at page 14, *for* line 31, the following be *substituted*, namely:–

"enrolled first in the State Register and subsequently in the National Register maintained under this Act."

The question was put and the motion was adopted.

Clause 32, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 33, there is one Amendment (No. 38) by the Minister.

CLAUSE 33 – RIGHTS OF PERSONS TO PRACTICE

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 38) That at page 15, lines 12 to 14 be *deleted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 33, as amended, was added to the Bill.

Clauses 34 to 48 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 49, there is one Amendment (No. 39) by the Minister.

CLAUSE 49 – COGNIZANCE OF OFFENCES

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 39) That at page 19, line 27, *for* the word, "Ethic", the word "Ethics" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 49, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 50, there is one Amendment (No. 40) by the Minister.

CLAUSE 50 – POWER OF CENTRAL GOVERNMENT TO SUPERSEDE COMMISSION

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 40) That at page 19, line 36, *for* the words, "one year", the words "six months" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 50, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 51, there is one Amendment (No. 41) by the Minister.

CLAUSE 51 – JOINT SITTINGS OF COMMISSION, NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY, NATIONAL COMMISSION FOR YOGA AND NATUROPATHY AND NATIONAL MEDICAL COMMISSION

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 41) That at page 20, line 19, the words, "Yoga and Naturopathy" be *deleted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 51, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 52, there is one Amendment (No. 42) by the Minister.

CLAUSE 52 – STATE GOVERNMENT TO PROMOTE PRIMARY HEALTHCARE IN RURAL AREAS

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 42) That at page 20, *for* lines 26 to 28, the following be substituted, *namely*:-

"52. Every State Government may, for the purposes of addressing or promoting public health, take necessary measures to enhance the capacity of the healthcare professionals."

State Government to promote Public health

The question was put and the motion was adopted.

Clause 52, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: If there is an Amendment, I will read that. ...*(Interruptions)*... If it is not listed, what can I do? In Clause 53, there are two Amendments; Amendments (Nos. 43 and 44) by the Minister.

CLAUSE 53 – POWER TO MAKE RULES

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 43) That at page 20, *for* lines 36 to 38, the following be *substituted*, namely:–

"(b) the manner of appointing members under clause (c) of sub-section (4) of section 4;"

(No. 44) That at page 21, *after* line 10, the following be *inserted*, namely:–

"(ia) the other factors under clause (d) of section 29A;"

The question was put and the motion was adopted.

Clause 53, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 54, there are four Amendments; Amendments (Nos. 45 to 48) by the Minister.

CLAUSE 54 – POWER TO MAKE REGULATIONS

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 45) That at page 22, *after* line 2, the following be *inserted*, namely:–

"(*ia*) the manner of admission of students to undergraduate courses under sub-section (4) of section 14;"

(No. 46) That at page 22, *after* line 5, the following be *inserted*, namely:-

"(ja) the manner in which a person with foreign medical qualification shall qualify National Exit Test under sub-section (4) of section 15;"

(No. 47) That at page 22, *after* line 47, the following be *inserted*, namely:–

"(zaa) the areas in respect of which criteria may be relaxed under the proviso to section 29A;"

[Shri Shripad Yesso Naik]

(No. 48) That at page 23, lines 16 to 18, be *deleted*.

The question was put and the motion was adopted.
Clause 54, as amended, was added to the Bill.
Clauses 55 to 58 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 1, there is one Amendment (No. 3) by the Minister.

CLAUSE 1 – SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 3) That at page 1, line 5 *for* the figure "2019", the figure "2020" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In the Enacting Formula, there is one Amendment (No. 2) by the Minister.

ENACTING FORMULA

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 2) That at page 1, the Enacting formula *for* the words, "Sixty-ninth", the words "Seventy-first" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In the Long Title, there is one Amendment (No. 1) by the Minister.

LONG TITLE

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 1) That at page 1, in the long title *after* the word, "accessible", the word "affordable" be *inserted*.

The question was put and the motion was adopted.
The Long Title, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: After all the clauses have been disposed of, now, the Minister to move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: One minute. Mr. Jairam Ramesh, what were you saying? You said that Clause 14 is not there in the Bill.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, first of all, we are dealing with two separate Bills.

MR. CHAIRMAN: I am coming to the second Bill now.

SHRI JAIRAM RAMESH: Yes, Sir. I may have taken second Bill's Amendments in the first Bill. The mistake may have been mine. I am going to check it and I will get back to you. But, Sir, the point is, every Clause is being amended. ...*(Interruptions)*... We don't know what is there. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: This is the system if the Government wants to amend it. ...*(Interruptions)*...

श्री श्रीपाद यसो नाईक: सर, हमने Amendments इसमें include कर दिए हैं।

श्री सभापति: श्रीपाद यसो नाईक जी, बिना सभापति की अनुमति के किसी को नहीं बोलना है, चाहे वे मंत्री हों या सदस्य हों। Opposition or supposition, this is the position which you have to understand. Only the Chair permits. I understand that there are so many Clauses which are being amended. Naturally, the Members also get confused sometimes. I don't deny that. Sometimes, it happens. But when there are so many Amendments, the system of democracy is that you have to move every Amendment, discuss it and then dispose it of. That is the system.

I shall now put the Motion for reference of the National Commission for Homoeopathy Bill, 2019 to a Select Committee of Rajya Sabha moved by Shri Husain Dalwai to vote.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up consideration of the National Commission for Homoeopathy Bill, 2019. The question is:

> That the Bill to provide for a medical education system that improves access to quality and affordable medical education, ensures availability of adequate and high quality Homoeopathy medical professionals in all parts of the country; that promotes equitable and universal healthcare that encourages community health perspective and makes services of Homoeopathy medical professionals accessible to all the citizens; that promotes national health goals; that encourages Homoeopathy medical professionals to adopt latest medical research in their work and to contribute to research; that has an objective periodic and transparent assessment of medical institutions and facilitates maintenance of a Homoeopathy medical register for India and enforces high ethical standards in all aspects of medical services; that is flexible to adapt to the changing needs and has an effective grievance redressal mechanism and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there is one Amendment (No. 4) by the Minister.

CLAUSE 2 – DEFINITIONS

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 4) That at page 2, *for* line 13, the following be *substituted*, namely:–

> "the use of biochemic remedies supplemented by such modern advances, scientific and technological development as the Commission may, in consultation with the Central Government, declare by notification from time to time;".

The question was put and the motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I have one question. I am looking at Amendments in the Homeopathy Bill.

MR. CHAIRMAN: Can we come to that particular Amendment?

SHRI JAIRAM RAMESH: Yes, in the Homeopathy Bill.

MR. CHAIRMAN: Which Amendment in the Homeopathy Bill? I am now at Clause 2.

SHRI JAIRAM RAMESH: You just now said that Clause 2. Why are you not taking Clause 1?

MR. CHAIRMAN: Clause 1 would be taken at the end.

SHRI JAIRAM RAMESH: Would you come to Clause 1 at the end?

MR. CHAIRMAN: That is the system. I also got the same doubt. Now, we shall take up Clause 3.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: If first Amendment is carried, the other things do not follow. In Clause 4, there are 14 Amendments, Amendments (Nos. 44 to 47) by Dr. T. Subbarami Reddy, Amendments (Nos. 53 to 57) by Shri Binoy Viswam, Amendments (Nos. 67 to 68) by Shri K.K. Ragesh and Amendments (Nos. 5 to 7) by the Minister. Now, Dr. T. Subbaramy Reddy, not present. Shri Binoy Viswam, not pressing. Shri K.K. Ragesh, are you moving?

SHRI K.K. RAGESH: Sir, this is on the increase of State representation. I move the Amendments.

CLAUSE 4 – COMPOSITION OF COMMISSION

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): Sir, I move:

(No. 67) That at page 3, line 38, *for* the word “five”, the word “ten” be *substituted*.

(No. 68) That at page 3, line 41, *for* the word “four”, the word “six” be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, the Minister.

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 5) That at page 3, line 14, *for* the word "twelve", the word "nineteen" be *substituted*.

(No. 6) That at page 3, line 38, *for* the word "five", the word "ten" be *substituted*.

(No. 7) That at page 3, *for* lines 41 to 43, the following be *substituted*, namely:-

"(c) six members to be appointed from amongst the nominees of the States and Union territories, under clause (*d*) of sub-section (*2*) of section 11, of the Advisory Council for a term of two years in such manner as may be prescribed.".

The question was put and the motion was adopted.
Clause 4, as amended, was added to the Bill.
Clauses 5 and 6 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: When a Minister says that Amendment is moved, that means, I have permitted. He is moving the Amendment. In Clause 7, there is one Amendment (No. 58) by Shri Binoy Viswam. Are you moving?

CLAUSE 7 – REMOVAL OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF COMMISSION

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I move:

(No. 58) That at page 5, line 24, *for* the words "by order", the words "after judicious consultation" be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.
Clause 7 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 8, there are two Amendments; Amendment (No. 48) by Dr. T. Subbarami Reddy and Amendment (No. 8) by the Minister. Dr. T. Subbarami Reddy, not present. Now, the Minister.

CLAUSE 8 – APPOINTMENT OF SECRETARY, EXPERTS, PROFESSIONALS, OFFICERS AND EMPLOYEES OF COMMISSION

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 8) That at page 6, line 10, *for* the words "quality assurance", the word "accreditation" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.
Clause 8, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 9, there are two Amendments; Amendment (No. 69) by Shri K.K. Ragesh and Amendment (No. 9) by the Minister. Shri Ragesh, are you moving?

SHRI K.K. RAGESH: Sir, again, the Centre has been made the appellate authority here. So, I am moving the Amendment.

CLAUSE 9 - MEETINGS OF COMMISSION

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I move:

(No. 69) That at page 6, line 33, *for* the words "Central Government", the words "Medical Appellate Tribunal for Indian System of Medicine and Homeopathy" be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, the Minister.

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 9) That at page 6, *for* lines 32 to 34, the following be *substituted*, namely:–

"(6) A person who is aggrieved by any decision of the Commission, except the decision rendered under sub-section (*4*) of section 30, may prefer an appeal to the Central Government against such decision within fifteen days of the communication of such decision.".

The question was put and the motion was adopted.
Clause 9, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 10, there are three Amendments. The Leader of the Opposition and Anand*ji*, we have to think about this. Members give Amendments. It comes in the Business and they are not there. So, naturally, we do not take them up for consideration. I understand that. That is the position. Should it be continued in future also? Just apply your minds. The Leader of the House and others also, think about it.

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, the Member is a bit depressed. He is retiring.

MR. CHAIRMAN: That is okay. I am not mentioning about him individually. I am talking of this system. …*(Interruptions)*…

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, he is a favourite Member of yours.

MR. CHAIRMAN: No, no. Every Member of this House is a favourite Member of mine. And favouritism varies in degrees depending on their performance.

Conduct and performance. In Clause 10, there are three Amendments; Amendment (No. 49) by Dr. T. Subbarami Reddy and Amendments (Nos. 10 and 11) by Shri Shripad Yesso Naik. Dr. T. Subbarami Reddy is not present. Now, Shripad Yesso Naik.

CLAUSE 10 – POWERS AND FUNCTIONS OF COMMISSION

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 10) That at page 6, line 37, *for* the word "necessary, in", the words "necessary regulations in" be *substituted*.

(No. 11) That at page 7, *after* line 5, the following be *inserted*, namely:–

"(ha) frame guidelines for determination of fees and all other charges in respect of fifty per cent of seats in private medical institutions and deemed to be Universities which are governed under the provisions of this Act;"

The question was put and the motion was adopted.
Clause 10, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 11, there are four Amendments; Amendment (No. 50) by Dr. T. Subbarami Reddy, Amendment (No. 59) by Shri Binoy Viswam and Amendments (Nos. 12 and 13) by Shripad Yesso Naik. Dr. T. Subbarami Reddy is not present. Shri Binoy Viswam, are you moving the Amendment?

CLAUSE 11 – CONSTITUTION AND COMPOSITION OF ADVISORY COUNCIL FOR HOMOEOPATHY

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I move:

(No. 59) That at page 7, line 19, *after* the word "Council", the words "who shall

be of administrative ability, impeccable integrity and scientific temper" be *inserted*.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Shripad Yesso Naik.

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move.

(No. 12) That at page 7, *for* lines 22 and 23, the following be *substituted*, namely:–

"in that State, possessing qualifications in Homoeopathy, to be nominated by that State Government, and one member to represent each Union territory, who is the Vice-Chancellor of a University in that Union territory, possessing qualifications in Homoeopathy, to".

(No. 13) That at page 7, *for* lines 25 to 28, the following be *substituted*, namely:–

"Provided that where the Vice-Chancellor possessing qualifications in Homoeopathy is not available, a Dean or Head of Faculty possessing qualifications in Homoeopathy shall be nominated;

(ca) one member to represent each State and each Union territory from amongst elected members of the State Homoeopathy Medical Council, to be nominated by that State Medical Council;

(cb) the Chairman, University Grants Commission;

(cc) the Director, National Assessment and Accreditation Council;".

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 59) moved by Shri Binoy Viswam to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendments (Nos. 12 and 13) moved by Shri Shripad Yesso Naik to vote. The question is:

(No. 12) That at page 7, *for* lines 22 and 23, the following be *substituted*, namely:-

"in that State, possessing qualifications in Homoeopathy, to be nominated by that State Government, and one member to represent each Union territory, who is the Vice-Chancellor of a University in that Union territory, possessing qualifications in Homoeopathy, to".

(No. 13) That at page 7, *for* lines 25 to 28, the following be *substituted*, namely:-

"Provided that where the Vice-Chancellor possessing qualifications in Homoeopathy is not available, a Dean or Head of Faculty possessing qualifications in Homoeopathy shall be nominated;

(ca) one member to represent each State and each Union territory from amongst elected members of the State Homoeopathy Medical Council, to be nominated by that State Medical Council;

(cb) the Chairman, University Grants Commission;

(cc) the Director, National Assessment and Accreditation Council;".

The motion was adopted.

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 12, there are two Amendments; Amendments (Nos. 14 and 15) by Shri Shripad Yesso Naik.

CLAUSE 12 – FUNCTIONS OF ADVISORY COUNCIL FOR HOMOEOPATHY

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 14) That at page 7, line 35, *for* the words "research and training", the words "training, research and development" be *substituted*.

(No. 15) That at page 7, line 39, *for* the words "training and research", the words "training, research and development" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 13, there is one Amendment (No. 51) by Dr. T. Subbarami Reddy; not present.

Clause 13 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 14, there is one Amendment (No. 60) by Shri Binoy Viswam. Are you moving the Amendment?

CLAUSE 14 – NATIONAL ELIGIBILITY-CUM-ENTRANCE TEST

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I move:

(No. 60) That at page 8, line 9, *for* the words "other languages", the words "other regional languages" be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.
Clause 14 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 15, there are two Amendments; Amendment (No. 61) by Shri Binoy Viswam and Amendment (No. 16) by Shri Shripad Yesso Naik. Shri Viswam, are you moving the Amendment?

CLAUSE 15 – NATIONAL EXIT TEST

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I move:

(No. 61) That at page 8, line 23, *for* the words "other languages", the words "other regional languages" be *substituted*.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Shripad Yesso Naik.

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 16) That at page 8, *after* line 27, the following be *inserted*, namely:–

"(*4*) Any person with a foreign medical qualification shall have to qualify National Exit Test for the purpose of obtaining licence to practice Homoeopathy as medical practitioner of Homoeopathy and for enrolment in the State Register or the National Register, as the case may be, in such manner as may be specified by regulations".

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 61) moved by Shri Binoy Viswam to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 16) moved by Shri Shripad Yesso Naik to vote. The question is:

(No. 16) That at page 8, *after* line 27, the following be *inserted*, namely:-

"(*4*) Any person with a foreign medical qualification shall have to qualify National Exit Test for the purpose of obtaining licence to practice

Homoeopathy as medical practitioner of Homoeopathy and for enrolment in the State Register or the National Register, as the case may be, in such manner as may be specified by regulations".

The motion was adopted.
Clause 15, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 16, there is one Amendment (No. 62) by Shri Binoy Viswam. Are you moving the Amendment?

CLAUSE 16 – POST-GRADUATE NATIONAL ENTRANCE TEST

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I move:

(No. 62) That at page 8, line 32, *for* the words "other languages", the words "other regional languages" be *substituted*.

The question was put and the motion was negatived.
Clause 16 was added to the Bill.
Clause 17 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 18, there are two Amendments; Amendment (No. 63) by Shri Binoy Viswam and Amendment (No. 70) by Shri K.K. Ragesh. Shri Binoy Viswam, are you moving the Amendment?

CLAUSE 18 – CONSTITUTION OF AUTONOMOUS BOARDS

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I move:

(No. 63) That at page 9, line 7, be *deleted*.

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I move:

(No. 70) That at page 9, *after* line 8, the following be *inserted*, namely:–

"(d) Medical Appellate Tribunal for Indian System of Medicine and Homoeopathy.".

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 63) moved by Shri Binoy Viswam to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 70) moved by Shri K.K. Ragesh to vote.

The motion was negatived.

Clause 18 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 19, there are three Amendments; Amendment (No. 64) by Shri Binoy Viswam, Amendment (No. 71) by Shri K.K. Ragesh and Amendment (No. 17) by Shri Shripad Yesso Naik. Shri Binoy Viswam, are you moving the Amendment?

CLAUSE 19 – COMPOSITION OF AUTONOMOUS BOARDS

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I move:

(No. 64) That at page 9, lines 15 to 19, be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri K.K. Ragesh. Are you moving your Amendment?

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I move:

(No. 71) That at page 9, *after* line 24, the following be *inserted*, namely:–

"The Medical Appellate Tribunal for Indian System of Medicine and Homeopathy shall consist of a Chairperson, who shall be a sitting or retired Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court, and four other members who shall have special knowledge in the medical profession and education, Indian Systems of Medicine, Homeopathy, and health administration.".

MR. CHAIRMAN: Now, the Minister.

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 17) That at page 9, *for* lines 18 and 19, the following be *substituted*, namely:–

"be an accreditation expert;".

MR. CHAIRMAN: I shall first put the Amendment moved by Shri Binoy Viswam to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Shri K.K. Ragesh to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No. 17) moved by the Minister, Shri Shripad Yesso Naik, to vote. The question is:

(No. 17) That at page 9, *for* lines 18 and 19, the following be *substituted*, namely:–

"be an accreditation expert;".

The motion was adopted.

Clause 19, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 20, there is one Amendment (No. 72) by Shri K.K. Ragesh.

DR. BANDA PRAKASH: Sir,...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You have not given any Amendment. ...*(Interruptions)*...

DR. BANDA PRAKASH: Sir, this is list that they have supplied. For Clauses 17 and 18, there is no Amendment. Sir, I am bringing this to your kind notice.

MR. CHAIRMAN: Right; I will go through it. Shri K.K. Ragesh, are you moving the Amendment?

CLAUSE 20 – SEARCH COMMITTEE FOR APPOINTMENT OF PRESIDENT AND MEMBERS

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I move:

(No. 72) That at page 9, line 34, *after* the words "Autonomous Boards" the words "Medical Appellate Tribunal for Indian System of Medicine and Homeopathy" be *inserted*.

The question was put the motion was negatived.

Clause 20 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 21, there are two Amendments, Amendment (No. 65) by Shri Binoy Viswam and Amendment (No. 18) by the Minister. Shri Binoy Viswam, are you moving the Amendment?

CLAUSE 21 – TERM OF OFFICE AND CONDITIONS OF SERVICE OF PRESIDENT AND MEMBERS

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I move:

(No. 65) That at page 9, line 37, *for* the words "four years", the words "three years" be *substituted*.

The question was put the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, the Minister.

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 18) That at page 9, line 36, *for* the word "held", the word "hold" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.
Clause 21, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 22, there is one Amendment (No. 66) by Shri Binoy Viswam. Are you moving the Amendment?

CLAUSE 22 – ADVISORY COMMITTEES OF EXPERTS

SHRI BINOY VISWAM: Sir, I move:

(No. 66) That at page 10, lines 1 to 4, be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.
Clause 22 was added to the Bill.
Clause 23 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 24, there is one Amendment (No. 19) by the Minister. Are you moving the Amendment?

CLAUSE 24 – MEETINGS OF AUTONOMOUS BOARDS

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 19) That at page 10, line 17, *for* the words "sixty days", the words "thirty days" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.
Clause 24, as amended, was added to the Bill.
Clause 25 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 26, there is one Amendment (No.52) by Dr. T. Subbarami Reddy. He is not present.

Clause 26 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 27, there is one Amendment (No. 20) by the Minister.

CLAUSE 27 – POWERS AND FUNCTIONS OF BOARD OF ETHICS AND REGISTRATION FOR HOMOEOPATHY

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 20) That at page 11, *after* line 19, the following be *inserted*, namely:-

"(d) exercise appellate jurisdiction with respect to the actions taken by a State Medical Council under Section 30.".

The question was put and motion was adopted.
Clause 27, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 28, there is one Amendment (No. 21) by the Minister.

CLAUSE 28 – POWERS AND FUNCTIONS OF MEDICAL ASSESSMENT AND RATING BOARD FOR HOMOEOPATHY

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 21) That at page 11, line 28, *after* the words "new medical institution", the words "or to start any postgraduate course or to increase number of seats," be *inserted*.

The question was put and motion was adopted.
Clause 28, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 29, there are nine Amendments, Amendments (No.22 to No.30) by the Minister. Are you moving the Amendments?

CLAUSE 29 – PERMISSION FOR ESTABLISHMENT OF NEW MEDICAL INSTITUTION

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 22) That at page 12, line 8, *after* the words "new medical institution", the words "or start any postgraduate course or increase number of seats" be *inserted*.

(No. 23) That at page 12, lines 20 and 21, *for* the words "six months", the words "three months" be *substituted*.

(No. 24) That at page 12, *for* lines 22 and 23, the following be *substituted*, namely:–

"Provided that before disapproving such scheme, an opportunity to rectify the defects, if any, shall be given to the person concerned.".

(No. 25) That at page 12, line 27, *for* the words "six months", the words "three months" be *substituted*.

(No. 26) That at page 12, line 29, *for* the words "six months", the words "three months" be *substituted*.

(No. 27) That at page 12, line 31, *for* the word "forty-five", the word "fifteen" be *substituted*.

(No. 28) That at page 12, line 32, *for* the word "thirty", the word "seven" be *substituted*.

(No. 29) That at page 12, line 34, *for* the word "forty-five", the word "fifteen" be *substituted*.

(No. 30) That at page 12, line 37, *after* the words "any other expert", the words "having integrity and experience in medical profession" be *inserted*.

The question was put the motion was adopted.
Clause 29, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, there is one Amendment (No.31) for insertion of New Clause 29A by the Minister.

INSERTION OF NEW CLAUSE 29A – CRITERIA FOR APPROVING OR DISAPPROVING SCHEME

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 31) That at page 12, *after* line 38, the following new clause be *inserted*, namely:–

"29A. While approving or disapproving a scheme under section 29, the Medical Assessment and Rating Board for Homoeopathy, or the

[Shri Shripad Yesso Naik]

Commission, as the case may be, shall take into consideration the following criteria, namely:–

(a) adequacy of infrastructure and financial resources;

(b) whether adequate academic faculty, non-teaching staff and other necessary facilities have been provided to ensure proper functioning of medical institution or would be provided within the time-limit specified in the scheme;

(c) whether adequate hospital facilities have been provided or would be provided within the time-limit specified in the scheme;

(d) such other factors as may be prescribed:

Provided that, subject to the previous approval of the Central Government, the criteria may be relaxed for the medical institutions which are set up in such areas as may be specified by the regulations."

The question was put and the motion was adopted.

New Clause 29A was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 30, there is one Amendment (No. 32) by the Minister.

CLAUSE 30 - STATE MEDICAL COUNCILS

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 32) That at page 13, *for* lines 15 to 19, the following be *substituted*, namely:–

"(4) A medical practitioner of Homoeopathy who is aggrieved by the decision of the Board of Ethics and Registration for Homoeopathy, may prefer an appeal to the Commission within sixty days of communication of such decision.".

The question was put and the motion was adopted.

Clause 30, as amended, was added to the Bill.

Clause 31 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 32, there is one Amendment (No. 33) by the Minister.

CLAUSE 32 – RIGHTS OF PERSONS TO BE ENROLLED IN NATIONAL REGISTER AND THEIR OBLIGATIONS THERETO

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 33) That at page 14, lines 8 and 9, *for* the words "enrolled in the National Register", the words "enrolled first in the State Register and subsequently in the National Register" be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.
Clause 32, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 33, there is one Amendment (No.34) by the Minister.

CLAUSE 33 – RIGHTS OF PERSONS TO PRACTICE

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 34) That at page 14, lines 33 to 35, be *deleted*.

The question was put and the motion was adopted.
Clause 33, as amended,was added to the Bill.
Clauses 34 to 44 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 45, there is one Amendment (No.73) by Shri K.K. Ragesh. Are you moving the Amendment?

CLAUSE 45 – OBLIGATION OF UNIVERSITIES AND MEDICAL INSTITUTIONS

SHRI K.K. RAGESH: Sir, I move:

(No. 73) That at page 18, *after* line 23, the following be *inserted*, namely:–

"(2) Every university and medical institutions covered under this Act shall ensure that fee for at least fifty per cent of seats shall be at par with the fees of Government medical colleges.".

The question was put and the motion was negatived.
Clause 45 was added to the Bill.
Clauses 46 to 48 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 49, there is one Amendment (No. 35) by the Minister.

CLAUSE 49 - COGNIZANCE OF OFFENCES

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 35) That at page 19, line 3, *for* the word "Ethic", the word "Ethics" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.
Clause 49, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 50, there is one Amendment (No. 36) by the Minister.

CLAUSE 50 – POWER OF CENTRAL GOVERNMENT TO SUPERSEDE COMMISSION

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 36) That at page 19, line 11, *for* the words "one year", the words "six months" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.
Clause 50, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 51, there is one Amendment (No. 37) by the Minister.

CLAUSE 51 - JOINT SITTINGS OF COMMISSION, NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEMS OF MEDICINE, NATIONAL COMMISSION FOR YOGA AND NATUROPATHY AND NATIONAL MEDICAL COMMISSION

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 37) That at page 19, line 42, the words "Yoga and Naturopathy" be *deleted*.

The question was put and the motion was adopted.
Clause 51, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 52, there are two Amendments, Amendment (No. 74) by Shri Husain Dalwai, Shrimati Viplove Thakur, Shri Madhusudan Mistry, Shri B.K. Hariprasad, Shri Tiruchi Siva and Shri M. Shanmugam and Amendment (No. 38) by the Minister. Husain Dalwai*ji*, are you moving the Amendment?

CLAUSE 52 - STATE GOVERNMENT TO PROMOTE PRIMARY HEALTHCARE IN RURAL AREAS

SHRI HUSAIN DALWAI: Sir, I move:

(No. 74) That at page 20, *for* lines 1 to 3 and marginal heading, the following be *substituted*, namely:–

"52. Every State Government may, for the purpose of addressing or promoting public healthcare, take necessary measures including the integration of different systems of medicines to enhance the capacity of the healthcare professionals and, if necessary, amend the relevant State law accordingly."

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, the Minister.

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 38) That at page 20, *for* lines 1 to 3, the following be *substituted*, namely:–

"52. Every State Government may, for the purposes of addressing or promoting public health, take necessary measures to enhance the capacity of the healthcare professionals.". State Government to promote Public health

The question was put and the motion was adopted.

Clause 52, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In, Clause 53, there are two Amendments; Amendments (Nos. 39 and 40) by Shri Shripad Yesso Naik.

CLAUSE 53 – POWER TO MAKE RULES

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 39) That at page 20, *for* lines 11 to 13, the following be *substituted*, namely:–

"(b) the manner of appointing members under clause (c) of sub-section (4) of section 4;".

[Shri Shripad Yesso Naik]

(No. 40) That at page 20, *after* line 29, the following be *inserted*, namely:–

"(ia) the other factors under clause (d) of section 29A;".

The question was put and the motion was adopted.
Clause 53, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In, Clause 54, there are three Amendments; Amendments (Nos. 41 to 43) by Shri Shripad Yesso Naik.

CLAUSE 54 – POWER TO MAKE REGULATIONS

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 41) That at page 21, *after* line 26, the following be *inserted*, namely:–

"*(ja)* the manner in which a person with foreign medical qualification shall qualify National Exit Test under sub-section (4) of section 15;"

(No. 42) That at page 22, *after* line 21, the following be *inserted*, namely:–

"(zaa) the areas in respect of which criteria may be relaxed under the proviso to section 29A;".

(No. 43) That at page 22, lines 37 to 39 be *deleted*.

The question was put and the motion was adopted.
Clause 54, as amended, was added to the Bill.
Clauses 55 to 58 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: If the Chairman has to read three times, and again approve it three times, and if he has the stamina, Members who are in such a big number, their voice should be a little louder. Now, in Clause 1, there is one Amendment (No. 3) by Shri Shripad Yesso Naik.

CLAUSE 1 – SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 3) That at page 1, line 4, *for* the figure "2019", the figure "2020" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In, the Enacting Formula, there is one Amendment (No. 2) by Shri Shripad Yesso Naik.

ENACTING FORMULA

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 2) That at page 1, line 1, *for* the word "Sixty-ninth", the word "Seventy-first" be *substituted*.

The question was put and the motion was adopted.
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In, the Long title, there is one Amendment (No. 1) by Shri Shripad Yesso Naik.

LONG TITLE

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, I move:

(No. 1) That at page 1, in long title, *after* the word "accessible", the words "and affordable" be *inserted*.

The question was put and the motion was adopted.
The Long Title, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Whatever amendments have come to my notice, I have put all of them for discussion and vote. Now, all the Clauses have been disposed off. Now, Mr. Minister to move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI SHRIPAD YESSO NAIK: Sir, move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: I think this is the Bill which has got the longest amendments that somebody has to study.

SHRI JAIRAM RAMESH: This is the Bill which has extraordinary large number of amendments. I can understand from where the amendments are coming; from the recommendations of the Standing Committee, absolutely no problem. Some of the amendments have come from the Report of the Standing Committee. But, Sir, the

[Shri Jairam Ramesh]

changes, the amendments go beyond the Standing Committee's recommendations and almost every Clause, in both the Bills, has undergone some modification. Sir, this is a very unsatisfactory way of looking at Bills.

MR. CHAIRMAN: The Bill is passed.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up discussion on the working of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Shri T.K.S. Elangovan...*(Interruptions)*... We shall sit a little late also. We will take up this. We have two more Ministries to be discussed. The other House is sitting till 12 O'clock. Please...*(Interruptions)*... No, no; it is for the Chair to decide. Don't make comments and counter comments. Shri T.K.S. Elangovan.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (Tamil Nadu): Sir, I thank you for giving me an opportunity to initiate the discussion on the working of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Sir, the purpose of the MSMEs is to take economy to the rural areas, to the backward areas, and to the areas where we need economic activity beyond agriculture. But, today, this sector is ignored by the Government. I can quote from the Budget of 2018-19. Sir, the Budget Estimates for 2018-19 for MSMEs was ` 1,215.06 crores; whereas, in the Revised Estimates, it has been reduced to ` 1,097.40 crores. Why has the Government revised it at a lower rate when it should have increased the allocation? That is one question. Sir, the major problem with the MSMEs is that they need funds. They need funds for upgradation of technology; they need funds for marketing; they need funds for training their people. But, the banks are not willing to fund these MSMEs. They are ready to fund major industries who take the money and run away. Whereas, these people, who want to give employment, instead of seeking employment, by investing their money from their own pockets and expecting the banks to support them, many of these industries are not supported by banks. That is the problem. I can quote one case in Tamil Nadu. We have SIDCO, Small Industry Development Corporation Industrial Estate in Tamil Nadu. In 2015 floods in Tamil Nadu, that industrial estate was inundated and many of these factories could